



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 1975/फाल्गुन 9, 1896

No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1975/PHALGUNA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ध्वज संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

बजट 1975-76

वित्त मंत्री का भाषण

28 फरवरी, 1975

महोदय,

1. 1. यह मेरा सोभाग्य है कि इस वर्ष इस महान सदन के सम्मुख बजट पेश करने का मुझे अवसर मिल रहा है ।

1. 2. इसे तैयार करने का काम कोई आसान नहीं था लेकिन मेरा बौद्धिक मेरे पूर्ववर्ती सम्मानित वित्त मंत्री ने हल्का कर दिया है जिन्होंने इस वर्ष के शुरू में बहुत सी सुधारात्मक उपाय लागू किये थे; इन कड़े उपायों का खर्चा कठिन आर्थिक परिस्थिति पर काफी असर पड़ा जो अभी तक हमारे राष्ट्र को आड़े आ रही थी ।

1. 3. इस अग्रसर पर घरेलू और बाहरी दोनों तरह की विभिन्न परिस्थितियों को व्योरेवार दुहराना जरूरी नहीं जितना हाल में हमारी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के ठीक ठीक चलते रहने में रुकावट पैदा की है। कीमतें जिस भयंकरता से बढ़ती रही और इसका जो विनाशकारी असर राष्ट्रों की सीमाओं को पार करता हुआ पड़ा उससे भारत जैसे विकासशील देशों पर ऐसे दबाव और मुसीबतें आयी जिनको सहन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। हमारी जनता के रहन सहन के स्तर और देश में वास्तविक आय के स्वरूप पर इसका काफी गम्भीर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा खराब बात है कीमतों का लगातार बढ़ते रहना जिसने बचत करने की क्षमता को क्षीण कर दिया है और हमारा अविष्य मुखद बनाने वाली योजनाओं को चालू रखने के लिए जिस पूँजी की इतनी सख्त जरूरत है उसका उपयोग करने में भारी कठिनाई पैदा कर दी है। 'आर्थिक समीक्षा' में इस कठिन समस्या का विश्लेषण कुछ विस्तार के साथ किया गया है और मौजूदा स्थिति की खास खास बातों की चर्चा की गयी है।

1. 4. मैं आशा करता हूँ कि जो बजट प्रस्ताव मैं पेश करूँगा उनका मूल्यांकन सम्मानित सदस्य इस पृष्ठभूमि को सामने रख कर करेंगे और अपना निर्णय देंगे।

1. 5. कोई पूछ सकता है कि इन प्रस्तावों को तैयार करने समय पीछे कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा आधारभूत दर्शन रहा है? क्या इस बजट में सरकारी खजाने की आय और खर्च में तात्समेल बिठालने की कोशिश कर कर्तव्य को पूरा हुआ समझ लिया गया है? या यह बजट अधिक निश्चयपूर्ण और सोद्देश्य तरीके से राष्ट्रीय उद्देश्यों को व्यापक आधार पर पूरा करने में सहायता प्रदान करता है।

1. 6. इसका उत्तर निश्चय ही स्पष्ट और सीधा है। जिन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा रही है उन तक पहुँचने के लिए हम बजट को निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। विकास, देश की सुरक्षा और सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि की कसौटी अब भी यह निर्णय करती है कि हम किस काम को पहले करें और किसे बाद में उठाये। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि हम कितना खर्च करें, किन कार्यक्रमों पर खर्च करें और खर्च के लिए किस तरीके से रकम जुटायी जानी चाहिए। समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार हमारे खर्च के स्वरूप और साथ ही रकम जुटाने के लिए साधन विधियों पर दिये जाने वाले बल के क्रम में हेर फेर हो सकती है—भले ही इस स्वरूप और क्रम को फिर से तैयार करने की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन जहाँ तक पीछे डालने वाली गरीबी से जनता को उबारने का काम है, जो बड़ी चिन्ता का विषय है और जिसे दूर करने का हमने बीड़ा उठा रखा है उस काम के प्रति निश्चय ही कभी कोई सन्देह या दो राये नहीं हो सकती। राष्ट्र को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में जो ठोस उपाय किये गये हैं उनमें बारी में मैं आपने भाषण में आगे बताऊँगा।

1. 7. स्वभावतः हमारी वित्तीय और मुद्रा संबंधी नीतियों का तत्काल उद्देश्य मूल्य वृद्धिकारी दबावों को दृढ़तापूर्वक नियंत्रण में रखना रहा है। बढ़ती हुई कीमतों के वातावरण में घिरी हुई अर्थव्यवस्था में रोटी, कपड़ा, मकान, लकड़ी, बिजली और यातायात के साधनों की तंगी होने की स्थिति में इनकी भारी मांग को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये जिनमें से कुछ अप्रिय और असह्य भी थे। योजना बनाने और नीति तैयार करने वालों के पास थोड़े ही समय में इन जरूरी चीजों की मांग और सप्लाई में सन्तुलन लाने के लिए कोई दूसरा वाय्वर उपाय नहीं था जिससे कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए साहस और धीरज की जरूरत है।

1. 8. फिर भी, मैं समझता हूँ कि कीमतों के गिरने के स्पष्ट संकेत देखकर अगर हमें थोड़ा भी सन्तोष नहीं होता तो इस निराशा का कोई इलाज नहीं है। 'आर्थिक समीक्षा' में मुख्य वस्तुओं की कीमतों के संकेत के बारे में कुछ व्यौरे दिये गये हैं। इनसे कुछ आशा बंधती है लेकिन सामान्यतः बुद्धिमानी यह है कि हम इस बात से सावधान रहे कि मूल्य-वृद्धि का बुखार पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है बल्कि इसके ताप के कुछ-कुछ कम होने के सिर्फ संकेत मिलने लगे हैं।

1. 9. लेकिन तब, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश की गरीबी की समस्याओं को सिर्फ कीमतों को आगे बढ़ने देने से रोकने से ही दूर नहीं किया जा सकता। हम उनका सामना सिर्फ विकास लाकर ही कर सकते हैं। तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था ही गरीबी को जड़ से दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है, निश्चय ही इसका यही एक समाधान है। इसलिए हमें जो क्षमता उपलब्ध है, उससे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तौर-तरीके ढूँढ़ निकालने हैं और इस क्षमता को उन क्षेत्रों में लगाना है जो गरीबों की आमदनी में वृद्धि करने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी पूंजी में वृद्धि करने, अपनी तकनालोजी और प्रबन्ध-व्यवस्था को सुधारने के लिए चहुँमुखी प्रयास करने होंगे। मैं इस समय जो बजट प्रस्ताव रख रहा हूँ उनमें इस आधार पर अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने की कुछ खास कोशिशें की गयी हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक स्थायित्व और इस आधार पर अधिक जीवन और शक्ति प्रदान करने वाली दीर्घकालीन योजना की अंग हैं।

II

2. 1. हम अपनी जनता की बुनियादी, कम से कम जरूरतों को कहां तक पूरा कर सकते हैं, यह मुख्य रूप से हमारी खेती की पैदावार पर निर्भर करता है। इस संबंध में, मैं कृषि में वृद्धि के खर्च को विकास खर्चों में पहला खर्च समझता हूँ। आजकल की खेती, उद्योग के साथ जुड़ी हुई है। बिजली की सप्लाई के आलाव उर्वरक, कीड़ों को मारने वाली दवाएं, खेती के औजारों से पैदावार पर उतना ही असर पड़ता है जितना कि बीजों और सिंचाई का पड़ता है। अपने उद्योग के जिन क्षेत्रों से इन चीजों की सप्लाई मिलती है हमें उन्हें ऊंची प्राथमिकता देना होगा।

2. 2. पिछले दो या तीन वर्षों में हमारी अर्थ व्यवस्था में जो विकृतियां आयीं वह खासतौर से 1971-72 से भारत में खेती की पैदावार में लगातार ढीलेपन के बने रहने के कारण आयीं। इस ढीलेपन के कारणों को सावधानी से देखा परखा गया है और हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक नयी जिदगी लाने के लिए अनेक उपाय ढूँढ़ निकाले हैं। अगली रबी की फसल के बढ़िया होन की संभावनाएं अच्छी हैं। लेकिन इससे हमारी उन कोणिकाओं में ढील नहीं आनी चाहिए जो हमारे खेती में लगी हुई जमीन और श्रम से और अधिक पैदावार लेने के लिए शुरू की हैं। पैदावार को लगातार बढ़ाते रहने के लिए हमें अनेक मोर्चों पर काम करना होगा।

2. 3. इस दिशा में सन्-पहला-काम जो हमें करना है वह अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अच्छे बीजों की सप्लाई करने के बारे में है। बड़े पैमाने पर अच्छे बीजों को पैदा करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय बीज परियोजना शुरू की गयी है। इस परियोजना में बीजों का उत्पादन, उनको प्रोसेस करना उनकी विक्री व खरीद करना और उनके बढ़िया किस्म को बनाये रखना शामिल है। अच्छे बीजों की मांग को पूर्ण तरह से पूरी करने के बारे में आत्म निर्भर बनाने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाकर क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बीज निगमों की स्थापना की जा रही है, अच्छे बीजों की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए कृषि विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जायगा। बीजों के उत्पादन और सप्लाई की व्यावहारिक कठिनाइयों को सुलझाने में वहां के

अनुसन्धान करने वालों प्रशिक्षण देने वालों और साथ ही वहाँ के विद्यार्थियों का सहयोग लिया जायगा। बीजों का सुधार करने के कारगर कार्यक्रम के लिए और अपात्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय भंडार बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए जितने भी खर्च की जरूरत होगी या जो और भी आवश्यकताएँ होंगी, उनको हर तरह से पूरा किया जायगा।

2. 4. दूसरे, नये यूनितों की परियोजना की लागत में वृद्धि होने के बावजूद उर्वरक उत्पादन करने वाले कार्यक्रमों को जारी रखा जा रहा है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिक उर्वरक पैदा करने की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र, सहकारी समितियों और गैर सरकारी क्षेत्रों का दायित्व निश्चित किया गया है जिससे हम विदेशों से इनका आयात करने पर, जो मंहगा पड़ता है और जिसका कोई निश्चय भी नहीं होता, अपनी परवशता को आशा है कि अगर पूरी तरह दूर न कर सके तो कम अवयव कर सकेंगे।

2. 5. तीसरे, फसलों की पैदावार की सिंचाई के लिए जो पानी जमीन पर ऊपर या उसके नीचे मिल सकता है उसका पूरा पूरा उपयोग करने के लिए बनाये गये कार्यक्रमों को शुरू किया जायगा। बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र कार्यक्रमों को खेती में काम आने वाले साधनों व सामग्री द्वारा पुष्ट किया जायगा जिसमें किसान नयी क्षमता का जल्दी से लाभ उठा सकें और जो समाज के लिए अधिक से अधिक लाभकारी हो। अन्तरीज्यीय न विवादों को जो दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से बिना किसी निर्णय पर पहुँचे अनेक कारणों से चलते चले आ रहे हैं, तुरन्त निबटाने के विचार से अब देखा-परखा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कुछक मामलों में प्रगति काफी अच्छी रही है। इन झगड़ों को न सुलझाने से हमारी नदियों का पानी बेकार जा रहा है और देश को जिस अधिक पैदावार की बेहद जरूरत है, उसकी बलि हो रही है।

2. 6. चौथे, कृषक सेवा समितियों को संगठित करने के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे किसानों को समय पर ऋण दिलाया जा सके और वह खेती में काम आने वाली चीजों को प्राप्त कर सकें, अपनी पैदावार बड़ा सके और बाजार में अपनी उपज की बिक्री कर सकें। इन समस्याओं की एक उच्चस्तरीय समिति ने जांच की थी। इस समिति ने सक्षम बहुदेशीय समितियाँ बनाने की स्कीम तैयार की है। यह समितियाँ केन्द्रीय सहकारी बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों से संबद्ध रहेंगी। इन सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और संबद्ध विभाग कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं जिससे किसानों को खास तौर से छोटे और बिचले किसानों के लाभ के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण देने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके आलाव इसमें खेती में काम आने वाली चीजों के रूप में दी जाने वाली सहायता और पैदावार को बढ़ाने और उसकी बिक्री के लिए व्यवस्था करने का काम भी शामिल है।

2. 7. कृषि क्षेत्र के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा नम्बर ऊर्जा के क्षेत्र का है। कोयले के राष्ट्रीयकरण से फायदे मिलने शुरू हो गये हैं। आशा है कि चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन 100 लाख टन बढ़ कर 880 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन पर पहुँच जायगा। मैं कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों की सराहना करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ अगर उनका उत्साहपूर्ण सहयोग न मिला होता तो शायद इतना उत्पादन हासिल करना संभव नहीं होता। इन खानों की प्रबन्ध-व्यवस्था का पुनर्गठन करने और इन खानों को जिन उपकरणों, स्पेयर पुर्जों और टेक्नीकल विशेषज्ञों की बहुत जरूरत थी उनकी सप्लाई करने से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक नींव सी डाल दी गयी है। कोयले के उत्पादन में जो बड़ी रुकावटें अर्थात् रेल यातायात और बिजली की कमी जो खास तौर से पूर्वी क्षेत्र में थी, उसे अब लगभग दूर किया जा चुका है। मौजूदा प्रगति को देखते

हुए आशा है कि अगले वर्ष कोयले का उत्पादन 100 लाख टन और बढ़ जायगा अर्थात् यह 980 लाख टन हो जायगा। कोयले का इतना उत्पादन होने से, देश के अन्दर की इसकी मांग को (जिसमें भट्टी में तेल की जगह कुछ अंश तक कोयले के इस्तेमाल के लिए कोयले की मांग शामिल है) पूरा किया जा सकेगा और हम कुछ कोयला विदेशों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी कमा सकेंगे जिसकी कि हमें बड़ी जरूरत है।

2. 8. कच्चे तेल और पेट्रोलियम से बनी चीजों की कीमतों के एक दम से चढ़ जाने का तुरन्त अंतर देश के व्यापार सन्तुलन पर निःसन्देह बुरा पड़ा। लेकिन इसके साथ ही, हमसे देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की अपूर्ण कोशिशों को जल्दी जल्दी पूरा करने, उनसे तेजी लाने की भावना पैदा हुई। एक साल की थोड़ी सी अवधि में, 1974-75 से 1975-76 के बीच, आशा है कि कच्चे तेल का उत्पादन 75 लाख टन से बढ़ कर 84 लाख टन हो जायगा अर्थात् 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां महत्व की बात यह देखना है कि हमने कितनी सफलता प्राप्त कर ली या देश में अगले 5 से 10 वर्षों के अन्दर इसके उत्पादन में भारी वृद्धि करने में कितनी बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खोल दिये गये हैं। बम्बई के पास समुद्र में तेल भंडार की खोज में जो सफलता मिली है उसे अब सभी जानते हैं। आशा है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1976 के उत्तरार्ध में यहां उत्पादन का पहला दौर पूरा कर लेगा और प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन कच्चा तेल निकलने लगेगा। आशा है कि 1980 तक यह उत्पादन 100 लाख टन होने लगेगा हालांकि इसके बारे में पक्की तौर से अनुमान लगाने में अभी कुछ समय लग सकता है। बंगाल और कच्छ के पास समुद्र में तेल का पता लगाने के लिए गहन सर्वेक्षण किया जा रहा है। यहां पर जो परिणाम अब तक प्राप्त हुए हैं वह उत्साहवर्धक लगते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस दशा में जो तत्परता दिखायी है, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए।

2. 9. पिछले काफी दिनों से बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था और बिजली की कमी महसूस की जा रही थी जिसका व्यापक प्रभाव उद्योग और कृषि दोनों पर पड़ रहा था लेकिन हाल में इसके उत्पादन और वितरण में अच्छी प्रगति हुई है। समूचे बिजली उद्योग के ढांचे में व्यावसायिकता, कुशलता और दक्षता पर बल देते हुए तथा कर्मचारियों के लिए उनका दायित्व निश्चित करते हुए फिर से सुधार किया जा रहा है। इन उपायों के फलस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में बिजली पैदा करने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को फिर से सक्रिय बनाया जा रहा है और राज्य बिजली बोर्डों को अपने प्रबन्ध की व्यावसायिक बनाने मरम्मत सेवाओं की व्यवस्था करने और अपने कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने में सहायता दी जा रही है। इन कार्यक्रमों से और हाल में जो सफलताएं प्राप्त की गयी हैं उनसे हाल के वर्षों की अपेक्षा बिजली की सप्लाई के सुधरने के संकेत मिलते हैं। सरकार देश में कोयले की खानों के प्रमुख क्षेत्रों में खानों के सिरे पर कई बड़े-बड़े तापीय बिजली घर बनाने की संभावना पर तेजी से विचार कर रही है। केन्द्र द्वारा स्थापित इन बड़े बिजली केन्द्रों से संघ सरकार को पावर की सप्लाई में आने वाले क्षेत्रीय असन्तुलन को कुछ हद तक कम करने, इसकी सप्लाई में भारी वृद्धि करने, और जरूरत के अनुसार बिजली के उत्पादन और वितरण की समस्या के बारे में अधिक युक्तिपूर्ण तरीका अपनाने में सहायता मिलेगी।

2. 10. निवेदन है कि इस बजट की सबसे प्रमुख विशेषता इन जुड़वां प्राथमिकताओं पर अर्थात् अन्न और ऊर्जा और साथ-साथ अन्य पोषक सुविधाओं पर स्पष्ट रूप से जोर देना है और दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने के पहले इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि के लिए पर्याप्त रकम निश्चित करना है। विकासशील देशों में योजना तैयार करने और नीति का निर्माण करने वालों के सामने यह एक अनिवार्य और कभी-कभी निर्मम दायित्व होता है जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है।

चाहे साधनों का कितना ही अभाव या आवश्यकताएं कितनी ही क्यों न हों। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इस बजट में ग्रथव्यवस्था के अन्न और ऊर्जा क्षेत्रों को दूसरे बाकी क्षेत्रों की थोड़ी बहुत उपेक्षा का जोखिम लेकर जो सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी है, सम्मानित सदस्य उसकी पुष्टि करेंगे। यहां मैं यह और कह दूँ कि ऐसा करने में हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में बतायी गयी पूजी लगाने की बुनियादी नीति का पालन कर रहे हैं।

2. 11. स्पष्ट रूप से प्राथमिकता देने की यह कोशिश केन्द्रीय बजट तक ही सीमित नहीं रहेगी। राज्यों की सरकारों से 1975-76 की उनकी आयोजनाओं के आकार और स्वरूप पर विचार करते समय यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि कृषि, सिंचाई और बिजली के क्षेत्र की आवश्यकताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय और उसके बाद जो कुछ बाकी बचे उसे ही दूसरे अन्य क्षेत्रों में वितरित किया जाय। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के इस व्यापक ढांचे में अपनी-अपनी योजनाओं को तैयार करने में राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों ने हादिक सहायता और सहयोग देना स्वीकार किया है, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ।

2. 12. ऊंची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश करते समय हमें दो अन्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं—पहली बात का संबंध उत्पादन के मानवीय और भौगोलिक पक्ष से है और दूसरी बात यह है कि जो चीजें हम पैदा करें उनका समुचित वितरण होना चाहिए। हमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते रहना होगा जहां पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है या जो क्षत्र पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। उत्पादन की समस्या, आय और रोजगार में वृद्धि की समस्या, असमानताओं को दूर करने की समस्या और सबके लिए खपत का कम से कम स्तर निश्चित करने की समस्या पर ज्यों का त्यों विचार करना होगा। इन शीर्षों के अधीन जो विशिष्ट कार्यक्रम बनाये जायेंगे उन्हें इस तरीके से बनाना चाहिए कि यह एक दूसरे के न केवल अनुरूप हों बल्कि एक दूसरे के लिए सहायक और एक दूसरे की पुष्टि करते हों। कृषि की पैदावार बढ़ाने का जो लक्ष्य हम बना रहे हैं वह इस तरह मशीनों से गुना-जोड़ करते हुए किसी जादुई अंक को प्राप्त करना नहीं है। किसानों में छोटे बड़े होने के अन्तर, एक क्षेत्र की पैदावार के दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा कम या ज्यादा होने के अन्तर के बारे में सोचना और उत्पादन के स्वरूप को सुनिश्चित करना, जो हमारे सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार हो, उतना ही महत्वपूर्ण है।

2. 13. अगर आर्थिक विकास के लाभ को बराबर वितरित करना है तो अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों और इलाकों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। इस प्रयोजन के लिए विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं, संभावनाओं और साधनों का सावधानी से विश्लेषण कर उसके आधार पर तैयार करना होगा। इस संबंध में, मैं भारत के सभी जिलों में प्राकृतिक साधनों के व्यापक सर्वेक्षण पर जोर देता हूँ। इससे हमें व्यवहार की दृष्टि से सार्थक योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता मिलेगी जिस हमसे स्थानीय रूप से जो साधन उपलब्ध है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकेंगे जैसा कि तेलंगाना में करीमनगर परियोजना में किया गया, जिसे सभी जानते हैं।

III

3. 1. आजकल जो तरह तरह के दुर्भग्य की भविष्यवाणियां सुनने में आ रही हैं उनके बावजूद भी मैं निश्चित रूप से आशावान हूँ कि आने वाले वर्षों में हमारे आर्थिक विकास में पर्याप्त तेजी से प्रगति होगी। लेकिन यहां मैं बता दूँ कि विकास की संभावनाओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए हमें लगातार परिश्रम करते रहने और हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। इस समय हम अपने देश में वित्तीय स्रोतों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

हमारे भुगतान सन्तुलन पर भी दबाव पड़ रहा है। जो काम हमें पूरे करने है, उनका कारगर तरके से पूरा करने के लिए, हमें अपना शक्ति भर अपने नियति में वृद्धि करने का कोशिश करना चाहिए और उत्पादन में काम आने वाले दुर्लभ वस्तुओं का जिनका हम बाहर से मंगाने हैं, कम से कम उपयोग करना चाहिए। बुनियादी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी लगाना जरूरी है लेकिन यह पूंजी गैर-स्फुटिकारी उपायों से जुटाया जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें बचतों का दर में वृद्धि करना ही चाहिए। मौजूदा खपत में अधिक वृद्धि को रोकने के उपाय के रूप में हमें मजदूरी और वेतन का अधिक युक्ति संगत ढांचा तैयार करना पड़ेगा जो मौजूदा ढांचे का अपेक्षा न्याय संगत हो और गतिशील अर्थ व्यवस्था में शिल्पों का बदलता हुई मांगों के अनुरूप हो।

3. 2. स्थायित्व के साथ तेजी से विकास करने का जो हमारी कोशिश है उसमें मैं सबसे ज्यादा महत्व इस बात पर देता हूँ कि हमारी जनता में जो अधिक कमजोर वर्ग है उसको रोजाना इस्तेमाल में आने वाला चीजों का बढ़ती हुई कीमतों और उनके अभाव से राहत दिलायी जाय। इसके लिए हमारे पास बुनियादी जरूरत की कुछ चीजों की कारगर सरकारी वितरण प्रणाली होनी चाहिए। इन चीजों की सप्लाई और अधिक सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन लोगों की जरूरतें पूरी की जानी चाहिए जिन्हें इस प्रणाली से लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाय। इससे जरूरत की चीजों की खरीद के लिए कुशल व्यवस्था का होना जरूरी हो जाता है। मुझे खुशी है कि चालू वर्ष में खरीफ की फसल की सरकारी खरीद में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। इससे और इसके साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज का आयात करने से निश्चय ही अगले वर्ष अनाज की सरकारी वितरण प्रणाली को कारगर तरीके से चलाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

3. 3. कपड़ा एक दूसरी जरूरी वस्तु है जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हाल में कपड़े की बीमार मिलों के राष्ट्रीयकरण का कानून बन जाने से सरकार ने 103 कपड़ा मिलों को अपने अधीन ले लिया जिनका प्रबन्ध पहले ही सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जा चुका था। इन मिलों को अपने अधीन लेने से कपड़ा तैयार करने और उसका वितरण करने के काम को ठीक करने के लिए सरकार को एक और उपयोगी साधन मिला गया। सरकार कुछ और उपायों पर भी विचार कर रही है जिनसे निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन सुनिश्चित हो सके और यह कपड़ा समाज के उन वर्गों तक पहुंच सके जिनके लिए यह तैयार किया जाता है।

3. 4. चूंकि साधनों का अभाव है इसलिए सबसे ज्यादा बल उत्पादकता में वृद्धि करने पर दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा काम है जिसमें समूचे सुधार की जरूरत सरकारी प्रशासन और उद्यमों का प्रबन्ध, दोनों क्षेत्रों में है। मुझे पूरी आशा है कि हाल में जो नयी व्यवस्था शुरू की गयी है जैसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों की प्रणाली, कार्यानुसार बजट बनाना और मानीट्रिंग व सूचना पर अधिक बल देना, उससे सरकारी प्रशासन के प्रबन्ध को और भी सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। मुझे यह देख कर खुशी है कि सरकारी क्षेत्र के सभी मैनेज्मेंट चर्चर उद्यमों में कार्मिक प्रशासन, प्रबन्ध विकास, सामग्री प्रबन्ध और प्रबन्ध सूचना प्रणालियों के क्षेत्रों में अधिक वैज्ञानिक नीतियां लागू कर तथा इसके अलावा उत्पादकता के नये तकनीकों का प्रयोग शुरू कर उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों के कार्यों में जो सुधार हुआ है उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

3. 5. मुझे विश्वास है कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि सरकार ने जो जोरदार उपाय किये उनसे हमें एक ऐसी स्थिति पर कारगर ढंग से काबू पाने में सफलता मिली जो अन्धाधुन्ध

मूल्य वृद्धि की स्थिति जैसी बन गयी थी। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए सरकार के गैर-विकास खर्च में कटौती की गयी, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के एक अंश को अस्थायी तौर पर जाम कर दिया गया, मुद्रापूर्ति में वृद्धि की दर में भारी कटौती की गयी और जमाखोरों और तस्कर व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी। इन उपायों के फलस्वरूप पिछले कुछ महीनों में कीमतें धीरे-धीरे लेकिन लगातार गिरती गयी हैं। जब हम विश्व के बहुत से दूसरे देशों में कीमतों को अब भी बढ़ते हुए देखते हैं तब ऐसी सफलता पाना कुछ कम श्रेय की बात नहीं लगती। खर्च पर जबरदस्त कटौती लगाने की इस नीति को जारी रखने के साथ-साथ, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों को और गैर सरकारी, क्षेत्रों को महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक पूंजी लगानी चाहिए। इस बजट के अन्य उद्देश्यों में से यह एक उद्देश्य है कि इस काम को पूरा करने में सहायता दी जाय। दूसरे और क्षेत्रों में थोड़े समय के लिए खर्च की दर नीची रहनी चाहिए लेकिन यही समय है कि हम आने वाले वर्षों में अधिक पूंजी लगाने के लिए एक भूमिका तैयार करें और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक छानबीन भी करें। हम इसी काम में लगे हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि हम इस समय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं में जिनसे हमें जल्दी ही लाभ हो सके पूंजी लगायें और उन परियोजनाओं को पूरा करें जिन पर काम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। यह भी जरूरी है कि हम देश में बचतों को बढ़ावा दें और पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन दें। इस बजट से हमारी कोशिश यह है कि हम इन्हीं विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करें।

3. 6. मैंने अभी पूंजी लगाने में बढ़ावा देने की जरूरत की चर्चा की है। पिछले कुछ दिनों हमारे पूंजी बाजार में, खास तौर से लाभांशों के वितरण पर रोक लगाने वाले अधिनियम के बाव कुछ मंदी आ गयी। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें यूनिटों की बिक्री की अपेक्षा पुनः खरीदने की दर काफी ज्यादा थी। सरकार ने इसलिए एक अध्यादेश निकाला जिसमें करों से कुछ छूट तथा अन्य सुधारात्मक उपायों की व्यवस्था की गयी थी। इससे स्थिति के सुधरने में बहुत सहायता मिली। पूंजी बाजार में सुधार लाने के लिए मेरा विचार शीघ्र ही लाभांशों पर प्रतिबन्ध अधिनियम संशोधन का प्रस्ताव लाने का है। इसमें यह व्यवस्था होगी कि अधिनियम में दी गयी सीमा से अधिक लाभांश चाहे न दिया जाय लेकिन उसे घोषित किया जा सकता है और यह स्थगित लाभांश मौजूदा अधिनियम के समाप्त होने पर दो वार्षिक किस्तों में दिया जायगा लेकिन इस पर कोई व्याज नहीं दिया जायगा। इससे पूंजी लगाने के लिए, खास तौर से नये शेयरों में पूंजी लगाने के लिए, और अच्छा वातावरण तैयार होगा।

3. 7. मुझे यह भी मालूम है कि हाल में पूंजी लागत में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे कुछ पूंजी प्रधान उद्योगों में जो हमारे भावी विकास के लिए बहुत जरूरी है, नयी पूंजी लगानी रुक गयी है। सरकार ने इस सवाल पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट के मिलते ही हम जल्दी ही उचित वित्तीय छूट देने की आवश्यकता के सवाल पर और इन क्षेत्रों में नयी पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के लिए कीमते तय करने की नयी नीतियां बनाने के बारे में विचार करेंगे।

3. 8. पिछले दो वर्षों के अनुभव से यह अच्छी तरह से पता चलता है कि काले धन के कारबार को उखाड़ फेंकने के कारगर उपायों को अर्थव्यवस्था में पर्याप्त स्थायित्व लाने और उपलब्ध राष्ट्रीय बचतों की रकम को ऊंची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाने की हमारी युक्ति का अनिवार्य रूप से आवश्यक अंग होना चाहिए। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि सरकार तस्कर व्यापार, जमाखोरी, काला बाजारी

और करो मे चोरी की प्रथा को निकाल फेंकने के लिए पूर्ण रूप में बचनबद्ध है और इस दिशा में अपने संकल्पों के प्रमाण दे चुकी है। इस प्रसंग में विभिन्न आर्थिक अपराधों को और सख्ती से कुचलने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है।

3. 9. इस प्रकार अपने दृष्टिकोण की रूप रेखा प्रस्तुत करने के बाद मैं अब 1974-75 के संशोधित अनुमानों और 1975-76 के बजट अनुमानों के बारे में कुछ ब्यौरे प्रस्तुत कर रहा हूँ।

IV

संशोधित अनुमान 1974-75

4. 1. चालू वर्ष के मूल बजट में 126 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान किया गया था। यह घाटा इस रकम तक बना न रह सका क्योंकि मूल बजट जिन अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया था उनमें से अधिकांश अनुमानों पर अर्थ वस्था में प्रतिकूल घटनाएँ होने, खास तौर से इस वर्ष कीमतों के असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण बुरा असर पड़ा। मैं इन कारणों को ब्यौरे से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।

4. 2. बजट में अन्न के लिए सरकारी सहायता के तौर पर 100 करोड़ रुपये रखे गये थे। अन्न की कठिन परिस्थिति को देखते हुए और 110 लाख टन के स्तर पर सरकारी वितरण की प्रणाली को बनाये रखने के लिए हमें 1974 में विदेशों से 55 लाख टन अन्न का आयात करना पड़ा। जो अन्न आयात किया गया उसकी लागत भी बहुत बढ़ गयी। अनुमान है कि इस वर्ष अन्न के लिए सरकारी सहायता 295 करोड़ रुपये तक की होगी।

4. 3. वर्ष 1974-75 के बजट में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन की जितनी व्यवस्था की गयी थी वह कीमतों के दिसम्बर 1973 तक के स्तर के आधार पर थी और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के खर्च को पूरा करने के लिए 120 करोड़ रुपयों की एक मुश्त व्यवस्था की गयी थी। अप्रैल, 1974 तक बढ़ने वाली कीमतों के आधार पर मंहगाई भत्ते की तीन किस्तें मंजूर की गयीं : लेकिन कीमतें सितम्बर, 1974 तक बढ़ती रहीं और मंहगाई भत्ते का जो फारमूला सरकार ने स्वीकार किया था उसके आधार पर मंहगाई भत्ते की तीन किस्तें और बकाया हो गयीं। मंहगाई भत्ता और अधिक दिये जाने से अर्थ व्यवस्था पर इसके बढ़ने हुए दबावों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत समझी गयी। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के परामर्श से यह तय किया गया कि वही किस्तें मंजूर की जाय जो 272 तक के औसत कीमत सूचक अंक के आधार पर हों। यह भी तय हुआ कि इस प्रकार जो रकम दिसम्बर, 1974 तक बकाया हों और नकद दी जाने वाली हों थोड़ी अवधि के लिए भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाय। मौजूदा कठिन परिस्थिति का सामना करने में कर्मचारियों ने जो सद्भावना और सहयोग व्यक्त किया उसके लिए मैं इनका आभार मानता हूँ। इससे मंहगाई भत्ते की छह किस्तों के कारण होने वाले खर्च को चालू वर्ष में बजट में 230 करोड़ रुपये तक सीमित रखने में सहायता मिली। यह अब भी बजट में की गयी 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था से 110 करोड़ रुपये अधिक है।

4. 4. चालू वर्ष में रक्षा-व्यय 2157 करोड़ रुपये होगा जब कि मूल बजट में 1915 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। मंहगाई भत्ते के कारण 95 करोड़ रुपये विये जाने के आलावा यह वृद्धि वेतन दरों में संशोधन किये जाने, पैट्रालियम से बनी चाजों की कीमतों के बढ़ जाने और दूसरी और रसद और यातायात का खर्च अधिक बढ़ जाने के कारण हुई।

4. 5. घाटे में वृद्धि का दूसरा कारण देश के विभिन्न भागों में पड़ने वाला सूखा और आने वाली बाढ़ थी। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं कि इस समय सूखा और बाढ़ के लिए केन्द्र की सहायता आयोजना सहायता में रखी गयी रकम में से सिर्फ पेशगी देकर या सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जन जातिय विकास योजनाओं आदि के अन्तर्गत दी जा रही है जिससे योजना में दी गयी प्राथमिकताओं के क्रम पर कोई असर न पड़े और इस सहायता से उत्पन्न और स्थायी परिसम्पत्तियाँ बनायी जा सकें। इस प्रकार दी गयी सहायता की पेशगी रकम को बाद के वर्षों में राज्यों को साधारण रूप से मिलने वाली आयोजना सहायता के रूप में दिखाया जायगा। इस नीति के अनुसार सूखा और बाढ़ सहायता के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिए पेशगी आयोजना सहायता के रूप में 55 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अलावा राज्यों को बहुसमुद्र बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य और सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सहायता मिल सकने की व्यवस्था की गयी है। इन खर्चों से और कुछ और जरूरी बायदों से जो हमने राज्यों को दे रखे हैं, राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता की रकम 161 करोड़ रुपये हो जायगी जिसमें 1973-74 के अल्प वचत संग्रह के बदले दिये जाने वाले ऋण की रकम भी शामिल है।

4. 6. घाटा अधिक हो जाने के जो दूसरे और कारण हैं उनका संबंध सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, उर्वरक, आयात और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय से है। कुछ उद्यमों के पास इतना पर्याप्त अभिशेष नहीं था कि वह सरकार से लिये गये ऋणों को चुका सकते। इसलिए यह जरूरी हो गया कि अनेक अंडर टैकिंगों को खास तौर से वेतन, मंहगाई भत्ते और तेल की लागत में वृद्धि के कारण खर्च पूरा करने के लिए 126 करोड़ रुपये की सहायता दी जाय जिसका अनुमान बजट में नहीं किया गया था।

4. 7. वर्ष 1974-75 के बजट में उर्वरकों की बिक्री व खरीद के लिए कोई निवल रकम नहीं रखी गयी थी। पूलसे दिये जाने वाले उर्वरक की बिक्री कीमत सिर्फ जून 1974 से बढ़ायी गयी थी। उर्वरकों की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए, बाद में विदेशों से काफी भारी कीमत पर लगभग 10 लाख टन उर्वरक का आयात करना पड़ा। विदेशों में उर्वरक की कीमत का भुगतान करने और राज्यों को दिये गये उर्वरक के बदले उनसे उसकी लागत वसूल करने में आ तौर से चार महीने लग जाते हैं। इस देरी के कारण विदेशों से मंगाये जाने वाले उर्वरक की रकम का भुगतान तो केन्द्रीय सरकार ने कर दिया लेकिन इस वर्ष के अन्त तक यह खर्च राज्यों से वसूल नहीं हो सकेगा। इसका बोझ केन्द्रीय बजट पर ही पड़ेगा। जैसी कि इस समय स्थिति है अनुमान है कि उर्वरक के लेन देन पर नकद खर्च लगभग 290 करोड़ रुपये होगा।

4. 8. जैसा कि सदन को मालूम है अगस्त, 1974 में अनेक कटौतियाँ की गयी थीं जिससे खर्च में काफी बचत हुई। फिर भी उर्वरक, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, इस्पात, बन्दरगाहें और कागज जैसे बुनियादी क्षेत्रों में योजना की स्कीमों के लिए 190 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी जिससे इनके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनके अनुसार काम जारी रह सके और लागत में बढ़ने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। अन्य क्षेत्रों में खर्च में जितनी कटौती करनी सोची गयी थी लागत का खर्च बढ़ जाने के कारण उतनी नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय योजना पर निवल खर्च 75 करोड़ रुपये बढ़ जायगा।

4. 9. इन सभी प्रतिकूल बातों के कारण बजट का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता लेकिन करों से होने वाली आय में वृद्धि होने के कारण स्थिति काफी हद तक सुधर गयी।

4. 10. आशा है कि सीमा शुल्क से बजट अनुमानों के 936 करोड़ रुपये की आय के अनुमान के बदले 1300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस वृद्धि का कारण

उर्वरकों, लोहा और इस्पात का भारी मात्रा में आयात किया जाना और उर्वरकों, मशीनरी और उपकरणों जैसी चीजों की कीमतों का अधिक बढ़ जाना है।

4.11. आय और कम्पनी करों से मूल बजट के 1370 करोड़ रुपये के अनुमान के बदले अब आशा है कि 1460 करोड़ रुपये की आय होगी।

4.12. संघ उत्पाद शुल्कों के संग्रह में, दूसरे वित्त विधेयक, 1974 में लगाये गये शुल्कों के कारण समायोजित बजट अनुमानों की अपेक्षा कोई खास वृद्धि नहीं होगी।

4.13. अपेक्षाकृत ऊँची आय वाले वर्गों पर हं. ज्यादा जोर रखने और सभी क्षेत्रों में कर तन्त्र को सामान्यतः कड़ा बनाने के जो उपाय किये गये थे उन में भारी लाभ हुआ है। राजस्व संग्रह करने वाले कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस कर्तव्य निष्ठा और उत्साह से कार्य किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ।

4.14. विदेशों से ऋणों के रूप में मिलने वाली रकम में लगभग 43 करोड़ रुपये की वृद्धि होती दिखायी पड़ती है जो मुख्यतः भारत सहायता संघ के सदस्य देशों द्वारा उन के ऋणों में छूट देने और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से आयोजना भिन्न ऋणों के मिलने के कारण हुई। विदेशी श्रोतों से मिलने वाले अनुदानों से होने वाली वास्तविक आय के संशोधित अनुमानों में 60 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी पड़ती है जिसका मुख्य कारण भारत को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघ के आपातकालीन सहायता कोष से मिलने वाली सहायता है जो उन देशों को सहायता देने के लिए बनाया गया है जिन पर तेल संकट का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत को इसके अलावा कुछ अन्य देशों से भी अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई।

4.15. देश में चीनी की सप्लाई की स्थिति के कुछ खराब होने का जोखिम उठा कर भी सरकार ने 5 लाख टन चीनी का निर्यात करने का कठिन निर्णय लिया। इससे हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति जहाँ सुधरी है वहाँ इससे होने वाली आय से जो 125 करोड़ तक की हुई है, बजट को भी लाभ पहुंचा है।

4.16. इन सब सुधारों के बावजूद, इस वर्ष के अन्त तक घाटा 625 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। लेकिन इसमें 330 करोड़ रुपये विदेशों से आयात किये गये अन्न और उर्वरक की कीमतों का भुगतान करने के लिए हैं। यह अन्न और उर्वरक हमारे पास स्टोक में हैं। यह खर्च शीघ्र ही वसूल कर लिया जायेगा। ये दोनों चीजें विदेशों में अपनी ही प्रारक्षित निधि से रकम निकाल कर खरीदी गयीं जिससे मुद्रापूर्ति में वृद्धि नहीं होती। इसलिए 330 करोड़ रुपये तक का घाटा मूल्य वृद्धिकारी नहीं है।

V

बजट अनुमान 1975-76

5.1. अर्थव्यवस्था में लगातार कमी के दाने रहने और बड़ी हुई कीमतों के असर की पृष्ठभूमि में अगले वर्ष के लिए बजट बनाना कोई आसान काम नहीं रहा। विकास कार्यों पर जहाँ सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वहाँ रक्षा, अन्न के लिए सरकारी सहायता और सामाजिक सेवाओं को बनाये रखने पर किये जाने वाले खर्च की जो आयोजना भिन्न खर्च है और जो काफी होता है, उपेक्षा नहीं की जा सकती। मैंने इस बजट में दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में जो

थोड़ी बहुत एक दूसरे से उल्टी पड़ती है, तालमेल बिठाने की कोशिश की है। यह दो आवश्यकताएँ हैं—मूल्य वृद्धि के दबावों को काबू रखने की अस्थायी आवश्यकता और विकास की गति जारी रखने की आवश्यकता जो उतनी ही महत्वपूर्ण है और जो मूल्य वृद्धि की समस्या का वास्तविक समाधान करती है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि विकास की कोशिशों में अगर कोई ढील हुई तो उससे भविष्य में हमारी समस्याएँ और भी बढ़ जायेंगी।

5. 2. करों की मौजूदा दरों पर अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाते समय हमसे इस वर्ष जैसी सन्तोषजनक आय हुई है उसका ध्यान रखा गया है। आय करों और कम्पनी करों से 1570 करोड़ रुपये और सब उत्पाद शुल्कों से 3500 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है। ग्याज कर से 60 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। लेकिन इस्पात का कम आयात किये जाने और उर्वरकों का सारा आयात चालू वर्ष के अन्त में होने के कारण सीमा शुल्कों से अगले वर्ष 50 करोड़ रुपये कम की आय होगी।

5. 3. बजट में 125 करोड़ रुपये की आय का अनुमान चीनी के निर्यात होने वाले लाभ के आधार पर लगाया गया है और अनुमान किया गया है कि अगले वर्ष चीनी का कम से कम उतना ही निर्यात होगा जितना कि इस वर्ष हुआ है।

5. 4. विदेशी ऋणों से उतनी ही रकम के प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है जितनी इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में दिखायी गयी है। पेट्रोलियम की चीजों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण हमारे भुगतान सन्तुलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव और भी बुरा पड़ता अगर ईरान, इराक और आबू धाबी से उदारतापूर्वक छूट नहीं मिलती। हमें इन देशों से तेल के ऋण मिलने की आशा है जिससे 1975-76 में बजट में 230 करोड़ रुपये का सहारा मिल जायगा।

5. 5 योजना के लिए रकम बचाने की भारी जरूरत को देखते हुए आयोजन-भिन्न खर्चों को कम से कम रखने की कोशिश की गयी है। लेकिन हमें उन क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा विकास कार्यों के अनुरक्षण और समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था करनी है। ऋण चुकाने और अगले वर्ष के लिए खर्च की दूसरी जरूरी मदों के अलावा रक्षा पर चालू वर्ष के 2157 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 2274 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1975-76 में अन्न के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली सहायता अनुमानतः 295 करोड़ रुपये होगी। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में सुधार होने का अनुमान किया गया है इसलिए आयोजना भिन्न सहायता के तौर पर इन उपक्रमों को चालू वर्ष में 217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में अगले वर्ष के लिए 78 करोड़ रुपये कम रखे जायेंगे। उर्वरकों के लेन-देन पर अगले वर्ष के लिए 140 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया है।

5. 6. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के सवाल पर उनके प्रतिनिधियों के साथ अगले कुछ सप्ताहों में चर्चा की जाने वाली है। यह प्रायः सभी लोग मानने लगे हैं चाहे यह अरुचिकर और कठोर भी हो कि मूल्यवृद्धि के कारणों को दूर करने के लिए कारगर तरीके ढूँढ़े जाने चाहिए। बजाय इसके कि कीमतों, आय और वेतन में बार बार तालमेल बिठाया जाय, जिससे सुनियोजित वृद्धि की प्रक्रिया में भारी रुकावट आती है। जिस देश में भारी बेरोजगारी हो, ल गों को पूरा रोजगार न मिला हुआ हो वहां पूरी तरह से रोजगार में लगे लोगों की चालू खपत की ओर अत्यधिक ध्यान देने से उस पूंजी में कमी आ जाती है जो किसी काम में लगायी जा सकती है और बेरोजगार व्यक्तियों के कष्टों को कम करने के लिए जिस रफ्तार से रोजगार के नये अवसर पैदा किये जा सकते हैं उस पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, आय में ऐसी वृद्धि से जो देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि के

अनुसार नहीं हो, अर्थव्यवस्था में मूल्य-वृद्धि के दबाव और बढ़ जाते हैं, इससे उन लोगों के आराम चैन को भी खतरा हो सकता है जिन्हें पूरी तरह से रोजगार मिला हुआ है। कीमतों के बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को जो कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें हालांकि मैं जानता हूँ लेकिन मैं हृदय से यह आशा करता हूँ कि जो हमारी बानचीत होगी उसमें इस व्यापक दृष्टिकोण को सामने रख कर महंगाई भत्ते पर विचार किया जायगा।

5. 7. अगले वर्ष के लिए योजना की आवश्यकताओं पर सावधानी से और विस्तार के साथ क्षेत्रवार विचार करने के बाद यह अनुभव किया गया कि अगर हमें दीर्घकालीन उद्देश्यों और तुरत जरूरी प्राथमिकताओं को पर्याप्त रीति से पूरा करना है तो केन्द्र, राज्य और संघ क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्र के बजट में कम से कम 3612 करोड़ रुपये रखे जाने चाहिए। बजट द्वारा जुटायी जाने वाली इस 3612 करोड़ रुपये की रकम में राज्यों और संघ क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 1054 करोड़ रुपये रखे गये हैं जिसमें पहाड़ी और जनजातियों के क्षेत्रों की उपयोजनाओं का खर्च, उत्तर पूर्वी परिषद् की आवश्यकताओं को पूरा करना और ग्रामीण बिजलीकरण निगम के माध्यम से बिजली की स्कीमों के लिए सहायता देने पर होने वाला खर्च शामिल है। इसमें कुछ राज्यों को जिनके अपने साधन चालू वर्ष में दी गयी केन्द्र की सहायता के आधार पर काम पड़ सकते हैं, पेशगी के तौर पर विशेष योजना सहायता देने के लिए 100 करोड़ की रकम भी शामिल है जिससे सिंचाई और बिजली के बुनियादी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजी लगाना सुनिश्चित किया जा सके। बजट में केन्द्रीय योजना के लिए 2558 करोड़ रुपये की सहायता रखी गयी है। अगले वर्ष केन्द्रीय आयोजना का कुल खर्च 3154 करोड़ रुपया होगा जिसमें बजट के बाहर का खर्च भी शामिल है। राज्य और संघ क्षेत्र की योजनाओं पर 2806 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इस तरह 1975-76 के लिए योजना का कुल खर्च 5960 करोड़ रुपये रखा गया है जो आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो 1974-75 के योजना के 4844 करोड़ रुपये के खर्च से 23 प्रतिशत ज्यादा है।

5. 8. केन्द्रीय योजना के लिए बजट में 2558 करोड़ रुपये जो रखे गये हैं वह चालू वर्ष में संशोधित अनुमानों के 2129 करोड़ रुपये की अपेक्षा 429 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। मैं समझता हूँ कि पाँचवी योजना के मसौदे में जो लक्ष्य रखे गये हैं उन्हें सभी क्षेत्रों में पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से योजनाओं में लगायी जाने वाली पूंजी में भारी वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़े पैमाने पर घाटे की व्यवस्था करने से कीमतें और बढ़ेंगी जिससे योजना का मूल तत्व नष्ट हो जायगा और योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम को और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि मैं पहले जोर दे चुका हूँ, हमने चयनात्मक तरीका अपनाया है और खेती, बिजली, उर्वरक, कोयला, पेट्रोलियम जैसे बुनियादी क्षेत्रों को, सीमेंट और कागज और जहाज निर्माण जैसे जरूरी उद्योगों को और यातायात को बाकी सभी क्षेत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता दी है और बुनियादी क्षेत्रों की ऐसी परियोजनाओं के लिए भी प्राथमिकता दी गयी है जो अपेक्षाकृत ज्यादा अवधि से पूरी होती है।

5. 9. अर्थव्यवस्था का आधार चूँकि कृषि है इसलिए इस क्षेत्र में और ज्यादा पूंजी लगाने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है अर्थात् संशोधित अनुमान के 193 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 270 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसमें कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए 50 करोड़ रुपये, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये, छोट और सीमान्तिक किसानों के लिए 22 करोड़ रुपये, सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए 16 करोड़ रुपये, कृषि अनुसन्धान और प्रशिक्षण के लिए 23 करोड़ रुपये और सहकारी उर्वरक फैक्टरियों सहित सहकारिता क्षेत्र के लिए 43 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

5. 10. उर्वरक के उत्पादन के लिए चालू वर्ष में रखे गये 192 करोड़ रुपये की तुलना में इसमें 84 करोड़ रुपये की वृद्धि की जायगी। तंगन कारखाने का विस्तार, रामगुंडम, तलचर, हल्दिया और कोचीन फेज-II और कुछ नये प्लांट जैसे ट्राम्ब IV और V तथा भटिंडा और पानीपत और सिंद्री में एक नयी परियोजना के लिए पर्याप्त रकम रखी जा रही है।

5. 11. अगले वर्ष के बजट में केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के लिए बजट में 140 करोड़ रुपए रखे गये हैं जिसमें ग्रामीण बिजलीकरण परियोजना के लिए की गयी व्यवस्था भी शामिल है। चालू परियोजनाओं जैसे बदरपुर एक्सटेंशन, लोकटक, बैरास्पूल और अन्तर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइनों के लिए पर्याप्त रकम रखी गयी है। इसके अलावा राज्य योजनाओं में बिजली के लिए 900 करोड़ रुपयों की कुल व्यवस्था की जायगी।

5. 12. इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के 141 करोड़ रुपये की रकम में भारी वृद्धि कर बजट में कोयले के लिए 229 करोड़ रुपये रखे गये हैं। कोयला खनन प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड के लिए भी अधिक रकम रखी गयी है जिससे पांचवीं योजना के अन्त तक 1350 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा हो सके। नेवेली में लिगनाइट के उत्पादन को 45 लाख टन के स्तर पर बनाये रखने के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

5. 13. पेट्रोलिएम और पेट्रोकेमिकल्स के लिए बजट में जो रकम रखी गयी है उसे 1974-75 के संशोधित अनुमानों के 60 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ा कर 1975-76 के लिए 170 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इंडिया और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन के लिए की गयी व्यवस्था में भारी वृद्धि की जायगी। जैसा कि सदन को मालूम है चालू वर्ष में तेल उद्योग के विकास के लिए एक उपकरण लगाया गया था और तेल के क्षेत्र का विकास करने के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं में समन्वय करने के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड बनाया गया था। बजट में जो रकम रखी गयी है उसके अलावा उक्त उपकरण से 61 करोड़ रुपये अगले साल इस बोर्ड को तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिए मिलेंगे।

5. 14. इस्पात क्षेत्र में खासतौर से बोकारो और भिलाई कारखानों का विस्तार करने के लिए व्यवस्था करते समय भविष्य में इस्पात की संभावित मांग को ध्यान में रखा गया है। कोरबा एन्यूमिनियम परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी रकम रखी गयी है।

5. 15. सीमेन्ट उत्पादन की जो परियोजनाएं इस मसल पर चालू हैं उनके लिए और तीन नयी परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष की योजना में पर्याप्त रकम रखी गयी है। नागालैंड में कांगडा का कारखाना बनाने के काम के लिए ऊंची प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रीय कंकड़ निगम ने जिन कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है।

5. 16. परिवहन और संचार के क्षेत्र में सभी मौजूदा बन्दरगाहों, जहाजरानी, जहाज निर्माण, विमानन परियोजनाओं की आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

5. 17. सामाजिक सेवाओं की उद्देश्य नहीं की गयी है। ग्रामीण और लघु उद्योगों, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, आवासन और नगरीय विकास तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए इस वर्ष के संशोधित अनुमानों की रकम से अधिक रकम रखी गयी है।

5. 18. जैसा कि सम्मानित नरेशों को मालूम है, दो स्कीमें पहली वेतन वृद्धि और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की आधी रकम को अतिवर्ग रूप में जमा करने वाली स्कीम और दूसरी आय-कर देने वालों की आय के कुछ प्रतिशत अंश की अतिवर्ग जमा स्कीम, पिछली जुलाई से शुरू की गयी थी। यह स्कीमें मुद्रापूर्ति में भारी वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था में आये गंभीर असन्तुलन को रोकने के लिए जरूरी थी। हमें खुशी है कि इन उपायों से और कुछ दूसरे उपायों से जो हमने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए किये कीमतों को स्थिर करने में सहायता मिली है। सरकार का ध्यान जहां लगातार मूल्यवृद्धि को रोकने में लगा हुआ है वहां यह भी जरूरी है कि विकास कार्यों को जारी रखा जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था के जरूरी क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक से वहां पर 1975-76 में जमा होने वाली अवरुद्ध रकमों के आधार पर लगभग 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाय।

5. 19. हम रकम को हिाब में लेने पर, 1975-76 की योजना के लिए बजट में 3612 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जिसमें 464 करोड़ रुपयों का घाटा होगा। सम्मानित सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मैं इस घाटे को किस प्रकार पूरा करूंगा।

Budget 1975-76

Speech of

Minister of Finance

28th February, 1975

1.1. It is my privilege this year to present the budget to this august House.

1.2. Its formulation has been no easy task; but my burden has been lightened to some extent by my distinguished predecessor in office who had applied many correctives earlier in the year; these severe measures had a distinct impact on an admittedly difficult economic situation that our nation has of late been faced with.

1.3. It is unnecessary for me on this occasion to recount in detail the variety of factors, both external and internal, which have interfered with the orderly implementation of our development plans and strategies in recent times. The virulence with which inflation has been spreading and its devastating impact across national boundaries, continue to impose on developing countries such as India burdens and hardships which we have been ill-equipped to withstand. The impact on the living standards of our people and on the pattern of real incomes within the country has been serious enough. What is even worse is the persistent rise in prices which has eroded the capacity to save and thus imposed a painful constraint on the flow of investible resources so urgently needed to sustain our plans for a better future. The 'Economic Survey' sets out in some detail the anatomy of this complex problem and the characteristic features of the current situation.

1.4. It is against this backdrop that I would like the Honourable Members to assess and to judge my budget proposals.

1.5. What, one might ask, has been the underlying approach—the basic philosophy—in framing these proposals? Is it merely an ostrich-like exercise to balance receipts and expenditure for the exchequer? Or does the budget seek more positively and purposively, to subserve larger national objectives?

1.6. The answer is, of course, clear and unequivocal. We *do* look upon the budget as an important tool for reaching our cherished socio-economic goals. Development, the security of our country and growth along with social justice continue to govern our priorities; these objectives determine our decisions on *how much* to spend; on *what* programmes to spend, and in *what manner* the resources are to be raised. The pattern of our outlays, as well as the relative weight of particular instruments in the raising of resources might vary—indeed, may well *need* to be deliberately fashioned afresh—from time to time, in response to changing circumstances and requirements. But about the over-riding concern and commitment to deliver the masses from grinding poverty there can, of course, never be any doubt or vacillation. I shall spell out a little later in my speech, the concrete steps contained in this budget to take the nation forward in this direction.

1.7. The immediate concern of our fiscal and monetary policies has been naturally to bring inflationary pressures firmly under check. A series of steps had to be taken—some of them unpalatable and unpopular—to restrain and discipline the demand pressures operating on the limited availabilities of food and fuel, of clothing and housing, of transport and power in an economy besieged by rising prices. In the short-run, there was no equally effective alternative open to the planners and policy-makers to balance demand and supply of these essential goods and services for containing inflation. These present a great challenge to our nation and call for courage and fortitude.

1.8. However, only incurable pessimism will, I think, bar us from acknowledging with some satisfaction, the fact that already there are visible signs of a downward trend in prices. The 'Economic Survey' provides some details of price trends for important commodities. They give room for some satisfaction, but ordinary prudence demands that we continue to be conscious of the fact that the fever of inflation has not been entirely cured; it has as yet only shown signs of some abatement.

1.9. But then, let us also remind ourselves that the problems of poverty in our country cannot be solved by merely holding the price line. We can meet them only through growth. A rapidly growing economy is the best insurance against perpetuation of poverty; indeed, it is the only solution. We have, therefore, to devise ways and means of stimulating production from the available capacity, and of adding to that capacity in sectors considered vital for improving income and consumption levels of the poor. This requires a multi-pronged drive to augment our capital, and improve our technology and management. The budget proposals, which I shall set forth presently, embody certain specific steps to provide the stimulus to the economy on these lines, as part of a longer-term strategy for stabilising and on that basis imparting greater viability and vitality to our economy.

II

2.1. Our ability to meet the minimum basic needs of our people depends crucially on the trend in agricultural production. It is in this light that I regard the claims of agricultural growth as the *first charge* on our developmental resources. Modern agriculture is interlinked with industry. Fertilisers, pesticides, agricultural implements and equipment, besides supply of power, determine agricultural productivity, as much as seeds and water. The sectors of our industry which supply these vital inputs to our agriculture, therefore, merit the highest priority.

2.2. The continued sluggishness of Indian agriculture since 1971-72 has contributed significantly to the distortions which have emerged in our economy in the last two or three years. The causes for this sluggishness have been carefully analysed; we have identified a series of measures directed towards imparting a new momentum to this vital sector. The prospects for the forthcoming rabi crop are encouraging. This should not, however, make us complacent in our drive for higher productivity from the land and labour employed in agriculture. A sustained increase in productivity will call for action on many fronts.

2.3. The *first* priority is, of course, the supply of good quality seeds of the high-yielding varieties. A major National Seeds Project for large-scale production of quality seeds has been launched. This project will cover production, processing,

marketing and quality control of seeds. Regional and State-level Seed Corporations, with a time-bound programme of self-sufficiency in meeting in full the demand for high quality seeds, are being established. Agricultural Universities will be involved in the work to ensure quality. The research and teaching staff as well as the students are to be involved in solving the practical problems of seed production and supply. Arrangements are also being made for an effective seed certification programme, and for the build up of national and local buffer-stocks to meet emergency needs. The financial and other requirements of this programme will be fully met.

2.4. *Secondly*, fertiliser production programmes are being pushed through, notwithstanding the escalation in project costs of the new units. The public, the cooperative, as well as the private sectors have been given a role in bringing to fruition additional fertiliser capacity during the Fifth Plan period so that dependence on imports—which is costly and unreliable at best—could be mitigated if not done away with altogether.

2.5. *Thirdly*, programmes designed to ensure optimum utilisation of surface and ground water to aid agricultural production will be pushed through. Command area programmes under major irrigation projects will be supported by sufficient inputs of men and materials so that the new potential is taken advantage of by farmers with the least delay and for maximum social benefit. Inter-State river disputes, which unfortunately have been dragging on without solution for a number of reasons in the past, are now being looked into with a special sense of urgency. As a result, the progress in some of the cases has been quite appreciable. Failure to settle these disputes is leading to waste of water and sacrifice of additional agricultural production that the country so desperately needs.

2.6. *Fourthly*, special efforts are being made to organise Farmers' Service Societies to provide credit to the farmers in time, to arrange for inputs and to help in processing and marketing of the produce. A high-powered group which examined this problem has formulated a scheme for the formation of viable multi-purpose societies linked to Central Cooperative Banks or commercial banks as the case may be. These recommendations have been accepted by the Government and the Departments concerned are working out a programme of action in order that the objective of timely and adequate supply of credit, backed by physical inputs and covering processing and marketing, is realised, particularly for the benefit of the small and medium farmers.

2.7. Next only in importance to the agricultural sector is the *energy sector*. The nationalisation of coal is beginning to yield results. During the current year the production of coal is expected to go up by about 10 million tonnes to a record level of 88 million tonnes. I would like to say a special word of appreciation and thanks to the workers in the coal mines; without their enthusiastic cooperation we could not have achieved the increase in production. Re-organisation in the management of mines and supply of much needed equipment, spares and technical expertise have laid the foundations for an expanding trend in coal output. Two of the major constraints on coal production, namely, shortage of rail transport and power, especially in the eastern sector have now been largely removed. With the present trend, it is expected that during the next year, coal production will go up by another 10 million tonnes, that is, to 98 million tonnes. At this level of production, it should be possible to meet the domestic demand in full (including partial substitution of coal for furnace oil); we might also perhaps export some quantity for earning much-needed foreign exchange.

2.8. The immediate impact of the steep increase in the prices of crude oil, and the petroleum products, was, no doubt, to strain the country's balance of payments severely. At the same time, this has given a new sense of urgency and momentum to our efforts to increase production of indigenous crude. The anticipated increase within as brief a period as one year, between 1974-75 and 1975-76, is from 7.5 million tonnes to 8.4 million tonnes, an increase of about 12 per cent. What is more important is the progress achieved and the potential that is opening up for a major break-through in the indigenous production within the next 5 to 10 years. The discovery of oil deposits in the structures known as Bombay High is already known. The Oil and Natural Gas Commission is expected to establish the first stage of production from Bombay High in the second half of 1976 with a yield of about one million tonnes per year. By 1980 production from this source might well reach the level of 10 million tonnes, though one may have to wait a little before making firm estimates. The Bengal and Kutch

off-shore basins are also being intensively surveyed and the preliminary results so far obtained appear encouraging. The dynamism exhibited by the Oil and Natural Gas Commission merits our appreciation.

2.9. After a period of stagnation and shortage with widespread consequences to both industry and agriculture, recent trends in the production and distribution of electricity also show a welcome improvement. The entire electricity industry is being restructured with accent on professionalism, efficiency, competence and precisely defined responsibility for the staff. As a result of these measures, there has been distinct improvement in the levels of power generation in the eastern region. The Central Electricity Authority is being reactivated and the State Electricity Boards are being helped to professionalise their management, to arrange for maintenance services and to improve staff skills. These programmes as well as recent achievements portend an easier power supply situation than has been the case in recent years. Government are also actively examining the possibilities of setting up at the pit heads of major coal fields in the country a number of super thermal power stations. These Centrally owned power stations would enable the Union Government to even out to some extent, the regional imbalances in power availability, augment the power supply substantially, and to bring about a more rational approach to the problem of generation and distribution of power in terms of real needs.

2.10. I wish to submit that the important feature of this Budget is a clear-cut identification of these twin priorities—food and energy with the supporting facilities—and the earmarking of adequate funds for the development of these two sectors in the first instance before taking up the claims of other sectors. This is the kind of inescapable and often cruel choice which planners and policy-makers in developing countries are called upon to make, beset as they are with scarce resources and multiple needs. I have no doubt that Hon'ble Members will endorse the over-riding priority that is being accorded in the Budget to the food and energy sectors of the economy, even at the risk of depriving some of the other sectors. I should, perhaps, add that in so doing we are observing the basic investment strategy underlying the draft Fifth Five Year Plan.

2.11. Nor would this clear-cut adherence to priorities be confined to the Central Budget only. In the course of the discussions with the State Governments for fixing the magnitude and pattern of the State Plans for 1975-76, it has been ensured that the requirements of agriculture, irrigation and power are met as a matter of first priority and only the balance of scarce resources distributed among other sectors. I would here like to express my gratitude to the Chief Ministers of State Governments and Union Territories for their willing support and co-operation in agreeing to frame their plans within this broad pattern of national priorities.

2.12. In striving to stimulate production in areas of high priority we have not lost sight of two other equally important considerations—one relating to the human and geographical aspects of production, and the other, to the proper distribution of the goods produced. The needs of relatively weak producers and backward regions will continue to receive special attention and support. The problem of production, of diffusion of income and employment, of reduction of inequalities, and of ensuring minimum consumption standards for all have to be looked at in their entirety. The specific programmes under these heads should not only be mutually consistent with each other, but should be so designed that they facilitate and reinforce each other. The increase in agricultural output that we are aiming at is thus not a matter of mechanically reaching a magic number. Considerations of balance between classes of farmers and of regions, and of ensuring a pattern of production that is in consonance with our socio-economic objectives are equally important.

2.13. If the fruits of economic development are to be equitably distributed, adequate attention will have to be paid to the problems of relatively backward regions and districts. To that end, development plans have to be drawn up on the basis of a careful analysis of local needs, potentialities and resources. In this connection, I would lay great emphasis on a comprehensive survey of natural resources in all districts of India. This would enable us to work out operationally meaningful plans and programmes to make optimum use of locally available resources along the lines of the now well-known Karimnagar project in Telangana.

III

3.1. In spite of the various prophecies of doom one hears these days, I am definitely optimistic that the pace of economic development will be considerably accelerated in the coming years. I must, however, point out that the full realisation of our growth potential will require sustained hard work and the utmost discipline on the part of all sections of the community. We are currently faced with an acute scarcity of domestic financial resources. Our balance of payments position is also under strain. In order to deal effectively with the tasks that lie ahead, we must do everything in our power to increase our exports, and economise in the use of scarce imported inputs. Higher investment in the key sectors is essential, but it must be financed in a non-inflationary manner. This means we must increase the rate of savings. As part of the strategy of discouraging excessive current consumption, we need to evolve a more rational wage and salary structure, which should be more equitable than the present structure, and also in conformity with the changing demands for skills in a dynamic economy.

3.2. In our quest for accelerated growth combined with stability I place the highest importance on protecting the more vulnerable sections of the population against shortages and the high prices of essential commodities. For this we must have a well-functioning public distribution system for certain basic essential commodities. There must be greater certainty of supply, and the system must in fact serve those whom it is meant to benefit. I, therefore, seek an expansion of the public distribution system, and this pre-supposes efficient arrangements for the procurement of the needed commodities. I am glad that procurement of kharif cereals during the current year has proceeded satisfactorily. This, combined with adequate imports, will certainly be of considerable help in the operation of an effective public distribution system of foodgrains in the coming year.

3.3. Cloth is another commodity that must be provided. With the recent enactment of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, Government have acquired 103 textile mills whose management had earlier been taken over by the Government. The acquisition of these mills provides Government with another very useful instrument to regulate the production and distribution of cloth. Government are now considering further steps to ensure that the production of controlled cloth is in line with the agreed target and that this cloth reaches those sections of the community for whom it is meant.

3.4. Since resources are scarce the utmost emphasis has to be laid on increasing productivity. This is a task which requires all round improvement both in public administration and the management of enterprises. I have every hope that recent innovations such as the system of internal financial advisers, performance budgeting, and greater emphasis on monitoring and information, will help to tone up the quality of public administration. I am happy to note the emphasis being laid on promoting higher productivity in all manufacturing public sector enterprises by applying more scientific policies in the fields of personnel administration, management development, materials management and management information systems and above all, through the introduction of modern productivity techniques. The improved performance of a large number of public sector enterprises is a testimony to growing productivity consciousness in the public sector.

3.5. I believe this House will concede that as a result of rigorous measures adopted by the Government, we have succeeded in combating what seemed to be a run-away inflationary situation. To achieve this, Government non-developmental spending was curtailed, increase in wages and a part of additional dearness allowance had to be temporarily frozen, the increase in the rate of money supply drastically brought down, and severe action taken against hoarders and smugglers. As a result of these efforts, for the last few months prices have been slowly but steadily coming down. This is no mean achievement when we consider that in most other countries around the world prices continue to rise. While continuing this policy of rigorous control on spending, there is also need, as I have mentioned earlier, for increased investment, both by the Central and State Governments, and the private sector, in important priority areas. It is one of the objects of this Budget to help achieve this. While the rate of spending in other areas must remain low, this is also the time to prepare the ground and do the necessary investigations to prepare for higher investment in later years. This we are engaged in. It is our purpose to invest now in projects in important areas

that will yield quick results, and complete those, in an advanced stage of implementation. Also important is the need to promote domestic savings and to stimulate investment. These various objectives we seek to achieve through the present Budget.

3.6. I have just mentioned the need to stimulate investment. The capital market has been depressed of late, particularly after the Restrictions on Distribution of Dividends Act. The Unit Trust of India had to face a situation in which repurchases were much higher than the sale of units. The Government, therefore, issued an Ordinance providing for certain tax relief and other remedial measures which have greatly improved the situation. For improving the capital market, I intend to introduce soon an amendment to the Restriction of Dividends Act which will provide that while dividends in excess of the various limitations laid down in the Act may not be paid, higher dividends can be declared, the deferred dividend being payable in two annual instalments, but without interest, when the present Act expires. These measures will improve the climate for investment, particularly in respect of new issues.

3.7. I am also conscious of the fact that in recent years, there have been steep escalations in capital costs which have acted as an inhibiting factor to new investment in certain capital intensive industries which are vital for our future growth. Government have appointed a high-level committee to go into this question. When the report of this Committee is received, we shall quickly examine the need for suitable fiscal concessions, and new pricing policies as a means of stimulating fresh investment in these areas.

3.8. The experience of the last two years amply demonstrates that effective steps to eliminate the black money economy must constitute an essential component of our strategy to impart a measure of stability to the economy, and to divert the available pool of national savings for high priority investments. I wish to reaffirm that Government is firmly committed to root out the evil practices of smuggling, hoarding, blackmarketing and tax evasion and have given evidence of their determination in this regard. In this context a separate law for dealing more severely with various economic offences seems to be a necessity.

3.9. Having thus outlined our approach, I will now give some details of the revised estimates for 1974-75 and the budget estimates for 1975-76.

IV

REVISED ESTIMATES 1974-75

4.1. The original budget for the current year envisaged a deficit of Rs. 126 crores. It has not been possible to adhere to this figure because many of the assumptions on which the original budget was framed have been affected by adverse trends in the economy, most particularly the phenomenal price rise this year. The various reasons for this I shall explain.

4.2. The provision in the budget for food subsidy was Rs. 100 crores. In view of the difficult food situation and the need to maintain the public distribution system at the level of 11 million tonnes, in 1974, we had to arrange for the import of as much as 5.5 million tonnes of foodgrains. The cost of imported foodgrains also went up greatly. Food subsidy during the year is now expected to amount to Rs. 293 crores.

4.3. The provisions for salaries of Central Government employees included in the budget for 1974-75 were based on the price level reached upto December 1973, and a lump sum provision of Rs. 120 crores was made to meet the cost of additional dearness allowance. On the basis of the price increase upto April, 1974, three instalments of dearness allowance were sanctioned. Prices, however, continued to rise till September 1974, and three further instalments of dearness allowance fell due on the basis of the dearness allowance formula accepted by the Government. In view of the likely unsettling effects of further dearness allowance payments on the economy, it was considered necessary to review these arrangements. Subsequently, in consultation with Government employees, it was decided to sanction instalments which fell due on the basis of the average price index upto 272. It was also agreed that arrears on this account upto December, 1974 payable in cash, would be deposited in the provident fund accounts for a short period. I must express my gratitude to the employees for their understanding and cooperation in meeting the present difficult situation. This

has enabled us to restrict the draft on the Budget on account of six instalments of dearness allowance to about Rs. 230 crores in the current year. This is still Rs. 110 crores more than the provision of Rs. 120 crores made in the Budget.

4.4. Defence expenditure for the current year will be Rs. 2157 crores as against Rs. 1915 crores in the original Budget. Apart from a liability of about Rs. 95 crores on account of dearness allowance, the increase is mainly due to revision of pay scales, rise in prices of petroleum products and the higher cost of provisions and transport.

4.5. Another reason for increase in the deficit has been the drought and floods with which many parts of the country have been effected. As Honourable Members are aware, Central assistance for drought and floods is being made available now only by way of advance release of Plan assistance, or assistance under the Drought Prone Areas Programme, Tribal Development Plans etc. so that plan priorities are not disturbed or distorted and that productive and durable assets are created through this assistance. Such advance assistance will be adjusted against the normal Plan assistance due to the States in the ensuing years. In accordance with this policy, advance Plan assistance of Rs. 55 crores has been allocated to the States for drought and flood relief measures in the current financial year. Apart from this, additional assistance has been made available to the States concerned under the Brahmaputra Flood Control Works and Drought Prone Areas Programme also. With these and certain other inescapable commitments towards the States, including release of loans against small savings collection in 1973-74, the additional assistance to the States will amount to Rs. 161 crores.

4.6. Other causes for the higher deficit relate to public sector enterprises, fertilizer imports and additional spending on core sector projects. A few of the enterprises did not have an adequate surplus to repay loans taken from Government. It, therefore, became necessary to provide additional assistance of Rs. 126 crores to a number of undertakings mainly because of increase in wages and dearness allowance and a higher cost of fuel had not been foreseen in the Budget.

4.7. The Budget for 1974-75 did not envisage any outgo on fertilizer transactions. The issue price from the pool was raised only from June 1974. Subsequently, in order to meet the urgent demand for fertilizers, an additional quantity of nearly 1 million tonnes had to be imported at considerably higher international prices. There is usually a time lag of about four months between the payment for purchases abroad and the cash recovery from State Governments of the cost of fertilizers issued to them. Because of this time lag, large fertilizer imports have been paid for by the Central Government, but their cost will not have been recovered from the States by the end of this year. The Central Budget, therefore, has to bear this burden. As of now, the estimate of cash outgo on account of fertilizer transactions is about Rs. 290 crores.

4.8. As the House is aware, a series of economy exercises were effected in August 1974, locating considerable savings in expenditure. However, additional allocations of Rs. 190 crores had to be made for Plan schemes in the core sectors like fertilizers, power, coal, petroleum, steel, ports and paper to maintain their schedules, and provide for escalation in costs. Economies anticipated in other sectors could not be realised in full due to steep rise in costs. As a result, the net expenditure on Central Plan will go up by Rs. 74 crores.

4.9. All these adverse factors would have raised budgetary deficit to a very high level, but for the fact that the position has been retrieved to a large extent by the buoyancy in tax receipts.

4.10. Receipts from Customs are expected to yield Rs. 1300 crores against the Budget estimates of Rs. 936 crores—the improvement being mainly on account of larger import of fertilizers, iron and steels and a large increase in the prices of items like fertilizers, machinery and equipment.

4.11. Income and Corporation Taxes are now expected to yield Rs. 1460 crores as against the original Budget estimate of Rs. 1370 crores.

4.12. There is not likely to be any appreciable increase in the collection of Union Excise duties over the Budget estimate, as adjusted by levies imposed in the Second Finance Act, 1974.

4.13. The strategy of concentration on higher income groups and a general tightening of the tax machinery in all branches has yielded good results. I would like to commend the devotion to duty and the zeal shown by the officers and staff of the revenue collecting agencies.

4.14. External receipts on account of loans, show an increase of nearly 43 crores mainly on account of larger receipts against debt relief from the members of the India Consortium, and larger non-project loans from IDA. Grants from external sources in the revised estimates in terms of actual receipts show an increase of about Rs. 60 crores mainly on account of assistance which India has received from EEC and the UN Fund for Emergency Relief for countries most seriously affected by the oil crisis, and additional assistance from some other countries.

4.15. Even at the risk of rendering the supply position in the domestic market a little difficult, the Government took the hard decision of allowing the export of nearly half a million tonnes of sugar. While improving our balance of payments position, this has also benefited the Budget to the extent of Rs. 125 crores by way of profits.

4.16. Even with these various improvements, the year may end with a deficit of Rs. 625 crores. However, nearly Rs. 330 crores of this is on account of payments for stocks on hand of imported food and fertilizers, which will soon be recovered. As both these commodities have been purchased abroad, by drawing down our foreign exchange reserves, there is no resultant increase in money supply and the deficit to the extent of Rs. 330 crores is, therefore, non-inflationary in character.

V

BUDGET ESTIMATES 1975-76

5.1. In the context of continuing shortages in the economy, and the impact of the price rise, framing the budget for the next year has not been an easy task. While developmental requirements must receive the highest priority, the draft on the budget for essential non-Plan requirements like Defence, the food subsidy, and the maintenance of social services cannot be ignored, and are substantial. I have endeavoured to balance two paramount but somewhat conflicting needs in this Budget—the short-term need to keep in check inflationary pressures, and the equally important requirement to sustain the tempo of development, which, in the ultimate analysis, is the real solution to the problem of inflation. I am only too well aware that any slackening of our development effort will compound our problem in the future.

5.2. The projections of receipts for next year at the existing rates of taxation take into account the satisfactory trends witnessed in the current year. Income and Corporation Taxes are expected to yield Rs. 1570 crores and Union Excise duties Rs. 3500 crores. Receipts from Interest tax are expected to be Rs. 60 crores. Customs receipts will, however, be less by Rs. 50 crores next year because of lower imports of steel, and the bunching of fertiliser imports towards the end of the current year.

5.3. The Budget also assumes a credit of Rs. 125 crores towards profits on export of sugar on the assumption that exports next year will at least be of the same order as this year.

5.4. Receipts from external loans are estimated at the same level as this year's revised estimates. The steep rise in the prices of petroleum products has greatly strained our balance of payments. The position would have been worse but for generous gestures by Iran, Iraq and Abu Dhabi. We hope to secure oil credits from these countries which will provide a support of Rs. 230 crores to the Budget during 1975-76.

5.5. In view of the pressing need to save maximum resources for the Plan, utmost care has been taken to contain non-Plan expenditure. But we have to provide for minimum needs in certain areas which are important for security, the maintenance of development work, and for safeguarding the interests of the weaker sections of society. Apart from debt servicing and other obligatory items of expenditure next year, Defence expenditure would be Rs. 2274 crores

as against Rs. 2157 crores in the current year. Food subsidy for 1975-76 is estimated at Rs. 295 crores. As the performance of public sector undertakings is expected to improve, non-Plan assistance to these undertakings will be less next year by Rs. 78 crores than the provision in the current year of Rs. 217 crores. The outgo on fertiliser transactions next year is estimated at Rs. 140 crores.

5.6. The entire question of dearness allowance increase to Central Government employees is to be discussed with their representatives in the next few weeks. It is now widely recognised that evolving effective measures for remedying the causes of inflation, though unpleasant and hard, should be preferred to frequent adjustment of prices, incomes and wages, which greatly hampers the process of planned growth. In a country where there is considerable unemployment and underemployment, an excessive preoccupation with the current consumption of those who are fully employed erodes investible resources and seriously affects the pace at which new employment opportunities can be created to alleviate the sufferings of those who are unemployed. Additionally an increase in monetary rewards, not justified by an increase in the country's productive capacity, accentuates inflationary pressures in the economy; this may also threaten the security currently enjoyed by those who are fully employed. While I am, therefore, aware of the hardship caused to Government employees by price rises, I earnestly hope that in our forthcoming discussions the dearness allowance question will be considered in this larger perspective.

5.7. After a careful and detailed sectoral review of the Plan requirements for next year, it was felt that the allocation in the Central Budget for the Central, State and Union Territory Plans should be at least Rs. 3612 crores, if our long-term objectives and urgent priorities are to be adequately fulfilled. This budgetary support of Rs. 3612 crores includes Rs. 1054 crores for States and Union Territories Plans, including the hill and tribal areas sub-Plans, the requirements of the North-Eastern Council and assistance for power schemes channelled through the Rural Electrification Corporation. It also includes Rs. 100 crores of special advance Plan assistance to certain States which may have gaps in resources on the basis of Central assistance at the current year's level, to ensure adequate investment in important projects in the core sectors of irrigation and power. Budgetary support for the Central Plan will be Rs. 2558 crores. The total Central Plan outlay next year inclusive of extra budgetary resources will be Rs. 3154 crores. The States and Union Territories Plans will be of the order of Rs. 2806 crores. Thus, the total Plan size for 1975-76 will be Rs. 5960 crores which in financial terms represents an increase of 23 per cent over the 1974-75 Plan of Rs. 4844 crores.

5.8. Budgetary provision for the Central Plan of Rs. 2558 crores represents a step up of Rs. 429 crores over the revised estimate of Rs. 2129 crores in the current year. I am conscious that a more substantial step up in the Plan investment to provide for achievement of draft Fifth Plan targets in all sectors would have been desirable from the long-term perspective of the economy. But we cannot forget that large scale deficit financing leading to further price increases will substantially erode the real content of the Plan and cause more damage to the programme of planned development. We have, therefore, as I stressed earlier, adopted a selective approach and given priority to key sectors of the economy like agriculture, power, fertilizers, coal, petroleum, essential industries like cement, paper and ship-building, and transport over all other sectors, and even over long gestation projects in the core Sectors.

5.9. As agriculture is the backbone of the economy, special care has been taken to step up the investment in this Sector substantially—from Rs. 193 crores in the Revised Estimates to Rs. 270 crores. The allocations include Rs. 50 crores for the Agricultural Refinance Corporation, Rs. 25 crores for drought prone areas programme, Rs. 22 crores to small farmers and marginal farmers development, Rs. 16 crores for command area development, Rs. 23 crores for agricultural research and education, and Rs. 43 crores for the cooperative sector, including the cooperative fertiliser factories.

5.10. There will be an increase of Rs. 84 crores in investment in fertiliser production over the current year's level of Rs. 192 crores. Adequate funds are being provided for Nangal Expansion, Ramagundam, Talcher, Haldia and Cochin Phase—II, and for several new plants such as Trombay IV and V. Bhatinda and Panipat and a new project at Sindri.

5.11. The Budget support for the power sector including support for Rural Electrification Corporation will be Rs. 140 crores in the next year. Substantial provision has been made for continuing projects like Badarpur extension, Loktak, Baira Siul and Inter-State Transmission Lines. Further, there will be an aggregate provision of the order of Rs. 900 crores in the State Plans for power.

5.12. Budget provision for coal represents a substantial increase from Rs. 141 crores in this year's Revised Budget to Rs. 229 crores. Coal Mines Authority and Bharat Coking Coal Ltd., have been allowed larger provisions to enable the achievement of the target of production of 135 million tonnes by the end of the Fifth Plan. Provision has also been made for stabilising the production of lignite at Neyveli at 4.5 million tonnes.

5.13. Budget provision for petroleum and petro-chemicals has also been greatly stepped up to Rs. 170 crores in 1975-76 as against Rs. 60 crores in 1974-75 Revised Estimates. There will be a considerable increase in the provision for the Oil and Natural Gas Commission, Oil India and Indian Petro-Chemicals Corporation. As the House is aware, a cess was levied in the current year for the development of the oil industry, and the Oil Industry Development Board was set up to coordinate the various development projects to be undertaken for oil development. A sum of Rs. 61 crores from this cess over and above the budgetary support will accrue to this Board next year to be used for oil development.

5.14. The provisions in the steel sector, particularly for Bokaro and Bhilai expansion have been fixed taking into account the likely demand for steel. Full provision has been made for completion of the Korba Aluminium Project.

5.15. Next year's Plan makes adequate provision for continuing projects for cement production and also for 3 new projects. The Paper Mill in Nagaland is being given high priority. Modernisation of textile mills taken over by the National Textile Corporation has also received special attention.

5.16. In the Transport and Communications sector, all continuing major ports, shipping, ship-building and aviation projects have been adequately catered for.

5.17. Social Services have not been neglected. Increased provision over the revised estimates for this year has been allowed for village and small scale industries, education, health, family planning, housing and urban development, and welfare of backward classes.

5.18. As Honourable Members are aware, two schemes, one for compulsory deposit of increases in wages, and 50 per cent of the additional dearness allowance, and another for compulsory deposit of a percentage of the income of income-tax payers, were introduced in July last. These were necessary to counter the serious imbalances created in the economy by the large increases in money supply. We are happy that these measures, along with other steps taken to curb inflation, have had a stabilising effect on prices. While it is the continuing concern of the Government to curb inflationary trends, it is equally important that development efforts should be sustained and adequate resources provided for investment in the vital areas of the economy. In view of this, it has been decided to take credit for a borrowing of about Rs. 100 crores from the Reserve Bank against the likely addition to blocked deposits which takes place in 1975-76.

5.19. Taking credit for this amount, the budgetary support of Rs. 3612 crores for the 1975-76 Plan will entail a resource gap of Rs. 464 crores. Honourable Members will be keen to know how I propose to deal with this deficit.

बजट भाषण 1975-76

भाग 'ख'

प्रत्यक्ष कर

1. 1. महोदय, मेरे प्रस्ताव सबसे पहले प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में हैं। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति की एक सिफारिश के आधार पर पिछले वर्ष व्यक्तिगत आय पर आय-कर की दरों को घटाया गया था। आशा की गयी थी कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से आय-कर मिलेगा। मेरा विचार है कि पिछले वर्ष जो नीति अपनायी गयी थी उसे अभी चालू रहना चाहिए। मैं इसलिए कम्पनी-भित्त करदाताओं के सम्बन्ध में आय-कर की दरों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ।

1. 2. इस समय अल्पजन-धारित औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में आय-कर की बुनियादी-दर, कर योग्य आय की पहले 2 लाख रुपये की रकम तक 55 प्रतिशत और बाकी आय पर 60 प्रतिशत है। बहु न-धारित कम्पनियों पर लागू कर की दरों के नमूने पर मैं इस व्यवस्था में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे इन अल्पजन-धारित कम्पनियों की समूची आय पर जहाँ सामान्य सीमान्तिक छूट देने के बाद कर योग्य आय 2 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है, 60 प्रतिशत की ऊँची दर लागू होगी। इस उपाय से पूरे वर्ष में 4 करोड़ रुपये और 1975-76 में 3 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। दूसरी श्रेणी की कम्पनियों के सम्बन्ध में आय-कर की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

1. 3. अनुसूचित बैंकों को मिलने वाले व्याज पर, व्याज-कर अधिनियम, 1974 के अधीन शुल्क लगाने से इन बैंकों से लिये जाने वाले ऋण का खर्च औसत में लगभग एक प्रतिशत बढ़ गया है। इस शुल्क के कारण गैर बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों को जनता से कहीं ज्यादा रकम, खास तौर से रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों के अर्पनाये जाने के संदर्भ में, जमा के तौर पर मिलने लग गयी है। इन कम्पनियों द्वारा जनता से ऋण लिये जाने पर कुछ रोक लगाने के उद्देश्य से कुछ सुधारात्मक उपाय किये गये हैं जिससे सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण आयोजन का उद्देश्य विफल न हो जाय। मैं इसलिए प्रस्ताव करता हूँ कि गैर बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों की कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय उनके द्वारा जनता की जमा पर दिये जाने वाले व्याज की केवल 85 प्रतिशत रकम को खर्च समझ कर, कर के प्रयोजन से छूट मिल सकेगी। इससे पूरे वर्ष में 10 करोड़ रुपये और 1975-76 में 7.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

1. 4. इस समय कर-अवकाश की छूट उन उद्योगों को, जो 1 अप्रैल, 1976 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगे और उन जगहों को दी जाती है जो उक्त तारीख से पहले इस्तेमाल में आने लगेंगे। मैं ऐसे मामलों में इस छूट को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह रियायत अनुमोदित होटलों को भी इस समय प्राप्त है चाहे वह किसी भी तारीख से अपना काम शुरू करें। मैं औद्योगिक उपक्रमों और जगहों की निस्वत इस रियायत को अनुमोदित होटलों को देने के लिए कोई उचित कारण नहीं मानता। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि यह छूट केवल उन्हीं अनुमोदित होटलों को दी जानी चाहिए जो 1 अप्रैल, 1981 के पहले अपना काम शुरू कर देंगे।

1. 5. इस समय शेयर होल्डरों की आय में कम्पनियों द्वारा अपने कर-अवकाश मुनाफे में से घोषित लाभांश की रकम की आय-कर के प्रयोजन से नहीं जोड़ा जाता और जिसके परिणाम-स्वरूप लाभांश का वितरण करने वाली कम्पनी की आय में कोई परिवर्तन होने पर उसके सभी शेयर होल्डरों के कर निर्धारण में संशोधन करना जरूरी हो जाता है। अनुभव से यह पता लगता है कि इस

उपबन्ध को लागू करना कठिन होता है क्योंकि सभी शेयर होल्डर एक जगह नहीं रहते। इसलिए मैं कम्पनियों द्वारा छूट की अवधि से सम्बन्धित कर-अवकाश मुनाफों में से अर्धा किये गये लाभानों के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। इस रियायत को समाप्त करने से शेयर होल्डरों को होने वाली हानि को पूरा करने के लिए मैं कम्पनियों के मामले में कर-अवकाश मुनाफे की राशि को नये औद्योगिक उपक्रमों, जहाजों, अथवा होटलों में लगायी गयी पूंजी के 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7.5 प्रतिशत वार्षिक करने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 6. कम्पनी-बचतों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की ओर मोड़ने के लिए मैं घरेलू कम्पनियों को उर्वरकों, कीड़े मारने की दवाओं, कागज और सीमेंट का उत्पादन करने वाली नयी कम्पनियों से प्राप्त होने वाले अन्तर्कम्पनी लाभानों को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 7. जसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, आय-कर अधिनियम की नवीं अनुसूची में शामिल प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के सम्बन्ध में, मशीनों और संयंत्र की लागत के 20 प्रतिशत की दर से प्रारम्भिक मूल्यह्रास की छूट दी जाती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कीड़े मारने की दवाओं के महत्व को देखते हुए मैं प्रारम्भिक मूल्यह्रास की छूट का लाभ कीड़े मारने की दवाइयों के उद्योग को भी देने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 8. वांछित क्षेत्रों में पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के एक अन्य उपाय के रूप में, मैं आय-कर की नवीं अनुसूची में शामिल प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगी नयी कम्पनियों के सामान्य शेयरों में लगायी गयी पूंजी को पांच वर्षों की अवधि के लिए धन-कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 9. वित्त विधेयक, 1974 में किये गये एक उपबन्ध के अन्तर्गत, उन जहाजों के मामले में जिनके लिए 1 दिसम्बर, 1973 से पहले आर्डर दिये गये हों, विकास छूट दी जा सकती है यदि ये जहाज 1 जून, 1975 से पहले प्राप्त कर लिये जायें। जहाजों को प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए मैं यह रियायत उन जहाजों के बारे में भी देने का प्रस्ताव करता हूँ जो 1 जनवरी, 1977 से पहले प्राप्त कर लिये जायें बशर्ते कि उनके आर्डर 1 दिसम्बर, 1973 से पहले दे दिये गये हों।

1. 10. मौजूदा कानून के अन्तर्गत, कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय, पुस्तकों के प्रकाशन के कारबार में होने वाले लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर की कटौती करने की छूट दी जाती है। यह रियायत 1975-76 के कर-निर्धारण वर्ष को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। मैं इस रियायत को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 11. हमारे विकास-प्रयत्नों को बचतों को बढ़ावा देकर ही जारी रखा जा सकता है। इसलिए भविष्य निधियों, जीवन बीमा आदि के माध्यम से की जाने वाली दीर्घकालीन बचतों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत इस समय जो रियायत उपलब्ध है, मैंने उसे उदार बनाने का निश्चय किया है जिससे कि ग्रहता प्राप्त बचतों के पहले 4,000 रुपये के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत की और इस प्रकार की बचतों के अगले 6,000 रुपये के 50 प्रतिशत की और शेष बचत के 40 प्रतिशत की कटौती की जाय। इस उपाय से राजस्व में एक पूरे वर्ष में 8 करोड़ रुपये की और 1975-76 में 6 करोड़ रुपये की कमी होगी।

1. 12. सरकारी भविष्य निधियों से बार-बार रकम निकाली जाती है। इसलिए मैंने उन सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए जो वर्ष के दौरान अपनी भविष्य निधि से कोई रकम नहीं निकालते उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक बोनस योजना लागू करने का निश्चय किया है।

यह बोनस किसी वर्ष के दौरान किये गये अंशदान पर दिया जायगा और 500 रुपया मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 3 प्रतिशत की दर से और 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 1 प्रतिशत की दर से दिया जायगा।

1. 13. सम्मानित सदस्य यह देखेंगे कि पूंजी लगाने के वातावरण में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गये हैं जैसे कर-अवकाश का विस्तार, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में लगे नयी कम्पनियों से प्राप्त अन्तर्कम्पनी लाभांशों को छूट, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगी कम्पनियों के सामान्य शेयरों को धन-कर से छूट और अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहन। साधनों की भारी तंगी के बावजूद, मैंने कर सम्बन्धी ये प्रोत्साहन देना उचित समझा है क्योंकि मेरा विचार है कि यदि हमें भविष्य में अपनी कठिनाइयों में वृद्धि नहीं करनी है तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहन देना जरूरी है। कर-सम्बन्धी इन उपायों से उन अन्य उपायों को बल मिलेगा जो सरकार ने कुछ बुनियादी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए किये हैं।

1. 14. मध्य वर्ग के उन परिवारों को जिन्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का भार सहन करना पड़ता है, कुछ राहत देने के लिए मैं व्यक्तियों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये खर्च के एवज में छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी विषयों में ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के विद्यार्थियों के मामले में छूट की राशि 1,000 रुपये प्रति बालक होगी और अन्य विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं अथवा चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी विषयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये प्रति बालक होगी। यह नयी रियायत उन व्यक्तियों के मामले में उपलब्ध होगी जिनकी कुल सकल आय 12,000 रुपया वार्षिक से अधिक नहीं होगी और हर हालत में दो बच्चों तक सीमित होगी। इस उपाय से राजस्व में एक पूरे वर्ष में 7 करोड़ रुपये की और 1975-76 में 4 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की कमी होगी।

1. 15. इस समय, पशु-पालन और कुक्कुट-पालन और डेरी-फार्मिंग से होने वाली आमदनी पर आय-कर नहीं लगता। कई बार ऐसी आमदनी को जिस पर अन्यथा कर लग सकता है, छूट प्राप्त आमदनी दिखा कर इस छूट का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं इस छूट को एक वर्ष में 10,000 रुपये तक सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे एक पूरे वर्ष में 2 करोड़ रुपये का और 1975-76 के वित्तीय वर्ष में 1.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

1. 16. मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के अन्तर्गत कर्मचारियों को अदा किये गये छंटनी सम्बन्धी मुआवजे को 20,000 रुपये की अधिकतम राशि तक, आय-कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 17. इस समय, वेतन पाने वाले करदाताओं के सम्बन्ध में आय-कर से छूट की कुछ सीमाएं लागू हैं जिनका सम्बन्ध मकान किराये भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायतों से है। छूट की इन सीमाओं को उदार बनाया जा रहा है। विदेशों में काम कर रहे भारतीय तकनीशियनों को भी कुछ कर-राहत देने का प्रस्ताव है।

1. 18. विदेशी जहाजरानी उपक्रमों के हिसाब-किताब अक्सर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इन पर कर-निर्धारण की प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इन उपक्रमों की आय, भारत में उत्पन्न यातायात से होने वाली उनकी सकल कमाई और भारत में प्राप्त अन्य कमाई के जोड़ के 7.5 प्रतिशत के बराबर मान ली जानी चाहिए। यह परिवर्तन कुछ अन्य देशों में विद्यमान प्रथा से मेल खाता है।

1. 19. इस समय किसी अनुमोदित ग्रेन्डुटी निधि में किये जाने वाले अंशदानों की, कर योग्य आमदनी का हिसाब लगाते समय कटौती कर दी जाती है। यह शंका प्रकट की गयी है कि सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार, जैसे कि वे इस समय लेखबद्ध हैं, करदाताओं द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में की गयी व्यवस्थाओं को भी कटौती के लिए अर्हता प्राप्त है। स्पष्टतः अभिप्राय यह नहीं है। शूक मालिक का नियंत्रण इन राशियों पर बना रहता है इसलिए मैं विशिष्ट रूप से यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ कि भावी ग्रेन्डुटियों के लिए ऐसी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कर-प्रयोजनों के लिए कोई कटौती नहीं की जायगी।

1. 20. व्यापार और व्यवसाय में तड़क-भड़क सम्बन्धी खर्च को कम करने के लिए, मैं उन आयातित कारों के सम्बन्ध में जो 28 फरवरी, 1975 के बाद प्राप्त की जायंगी, मूल्यह्रास छूट न देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ-साथ, मैं देश में बनी कारों के सम्बन्ध में, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, पूरे मूल्यह्रास की छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 21. इस समय, कृषि भूमि पर उगे वृक्षों को धन-कर से छूट नहीं प्राप्त होती। वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैं फलों के बागों और बागानों को छोड़ कर कृषि भूमि पर उगे वृक्षों के मूल्य को धन-कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

1. 22. कम्पनी कर के अन्तर्गत, इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 14.0 करोड़ रुपये और 1975-76 में 10.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। जो रियायतें दी गयी हैं उनके परिणामस्वरूप आय-कर के अन्तर्गत एक पूरे वर्ष में 13 करोड़ रुपये की और 1975-76 में 9 करोड़ रुपये की कमी होगी। 1975-76 में केन्द्रीय राजस्व पर इस कमी का प्रभाव 2.26 करोड़ रुपये होगा।

II

अप्रत्यक्ष-कर

2. 1. मैं अब अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों पर आता हूँ।

2. 2. हालांकि मुझे व्यापक तौर पर अनेक चीजों पर शुल्क लगाना पड़ा है लेकिन मैंने भरसक यही कोशिश की है कि समाज के अधिक कमजोर वर्ग के लोगों पर इनका कम से कम बोझ पड़े। मेरी यह भी कोशिश रही है कि मैं उन्हीं चीजों को चुनूँ जो समाज के ज्यादा श्रीमंती वर्ग के लोगों की खपत में आती हैं। मैंने यह भी कोशिश की है कि उन्हीं चीजों को चुना जाय जो हमारे निर्यात की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं जिससे उनकी देश में खपत कम हो और वह निर्यात के लिए उपलब्ध हो सकें तथा हम उससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकें।

उत्पाद-शुल्क

2. 3. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत के हाल में एकदम से चढ़ जाने से भारत को इस वस्तु का निर्यात बढ़ाने का, भले ही कुछ त्याग कर, एक बड़िया मौका मिला है। कुछ कम जरूरी चीजों पर चीनी के होने वाले उपयोग को कम कर और अधिक मात्रा में चीनी के निर्यात की व्यवस्था करने के विचार से मैं खुले बाजार में चीनी की बिक्री के बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 37½ प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस समय लेवी चीनी पर, जो कुल देशी खपत का 65 प्रतिशत भाग है, शुल्क की मौजूदा प्रभावी दर में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ जिससे हर व्यक्ति को उचित कीमत पर उसके कोटे के अनुसार चीनी निश्चय रूप से मिल सके। चीनी की खुली बिक्री पर शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि करने से 30.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 4. खंडसारी चीनी पर इस समय 17.5 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगता है। फिर भी आजाकल मिश्रित लेवी की एक योजना चालू है जिसके अधीन खंडसारी चीनी की वह यूनिटें जो इस स्कीम को स्वीकार कर चुकी हैं, प्रति सप्ताह चलने के लिए सेंट्रीफ्यूज के आकार और उनकी संख्या के आधार पर शुल्क के रूप में निश्चित रकम देती हैं। यह शुल्क रेगुलर बैक्यूम पैन वाली चीनी मिलों पर शुल्क प्रभार को देखते हुए काफी कम बैठता है। इसलिए मैं मिश्रित लेवी योजना को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। सभी खंडसारी यूनिटों पर केन्द्रीय उत्पाद व्यवस्था लागू होगी और यह 17.5 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क देगी। इस प्रस्ताव से मुझे आशा है कि 19.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 5. विभिन्न ज़ोनों में पैदा की जाने वाली चाय पर शुल्क में पिछले पांच वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस अवधि में भारतीय और लन्दन के बाजारों में चाय की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। मैं इसलिए इसको 10 से 15 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। ज़ोन I, II, IV और V में पैदा की जाने वाली खुली चाय पर और ज़ोन III की चाय पर इस समय सबसे ज्यादा शुल्क लगता है और इसकी उपज कम होने व खेती की लागत ज्यादा बैठने के कारण कुछ रियायत देने की जरूरत है। इस ज़ोन द्वारा पैदा की जाने वाली 90 प्रतिशत से ज्यादा चाय निर्यात की जाती है और चूँकि इन चायों की कीमत सबसे कम बड़ी है इसलिए इस ज़ोन के बुनियादी शुल्क को 10 पैसे प्रति किलोग्राम घटाने का प्रस्ताव करता हूँ। ज़ोन I, II, IV और V की चाय पर शुल्क में वृद्धि करने से राजस्व की प्राप्ति होने के अलावा विदेशों को निर्यात करने के लिए अधिक मात्रा में चाय मिलने लगेगी। मैं निर्यात की चाय को मौजूदा स्कीम के अधीन मिलने वाली छूट की दर को 75 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 85 पैसे प्रति किलोग्राम कर देने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे चाय पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से इसका निर्यात पर खराब असर न पड़े। इस प्रस्तावित वृद्धि से 3.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 6. सीमेंट विदेशी मुद्रा कमाने का एक दूसरा सभ्य साधन है और इसी कारण से मैं सीमेंट पर बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 15.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 7. कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनी चीजों का आयात करने के लिए अब भी उपलब्ध विदेशी मुद्रा की काफी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि जब तक ऊर्जा का संकट बना रहेगा, तब तक पेट्रोलियम की चीजों को और महंगा करना जरूरी है जिससे इनकी खपत में कमी की जा सके और इनका संभाल कर उपयोग किया जाय। इस पृष्ठभूमि में मोटर स्प्रिट पर शुल्क को 10 पैसे प्रति लिटर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। तेल से चलने वाले उपकरणों के स्थान पर कोयले से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए मैं भट्टी के तेल पर शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस शुल्क के लग जाने से भी पुराने उपकरणों की जगह नयी कुशल मशीनरी का इस्तेमाल उन प्रतिष्ठानों में भी होने लगेगा जो तेल से चलते हैं। विभिन्न उद्योगों में इसके इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए थोड़ी ही वृद्धि करने का निर्णय किया गया है जो 3 पैसे प्रति लिटर से भी कम है। लेकिन बिजली पैदा करने के काम में आने वाले लो सल्फर हेवी स्टाक को जैसा कि इस समय है, छूट मिलती रहेगी। पेट्रोलियम से बनी चीजों पर लगने वाले इन शुल्कों से कुल मिला कर 26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 8. कर्मशियल ग्रेड की तुलना में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड के एल्यूमिनियम के उत्पादन के अनुपात में हाल में कमी आयी है। ई० स० ग्रेड एल्यूमिनियम की कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के

लिए कमशियल ग्रेड के एल्यूमिनियम पर 2,000 रुपये प्रति टन उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। एल्यूमिनियम पर शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने लगेगा।

2. 9. मैं अब ऐसी चीज लेता हूँ जिसका सभी वित्त मन्त्रियों ने आसरा लिया है। तम्बाकू उत्पाद शुल्क दर समिति ने सिगरेट बनाने के काम में आने वाली तम्बाकू को छोड़ कर नान फिल्यू क्योर्ड अनमैन्यूफैक्चर्ड तम्बाकू पर एक समान टैरिफ दर लागू करने और इसके साथ तम्बाकू से बनी कुछ विशिष्ट वस्तुओं जैसे ब्रांड नामों से बेची जाने वाली बीड़ियों और खाने की तम्बाकू तथा सुंघनी पर कम दर से उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के अनुसार मैं नान फिल्यू क्योर्ड अनमैन्यूफैक्चर्ड तम्बाकू पर जिसमें सिगरेट बनाने के काम में आने वाली तम्बाकू शामिल नहीं है, कुल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक समान उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका आशय यह होगा कि बीड़ी की तम्बाकू के कुल उत्पाद शुल्क में 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम और हुक्का, खाने की तम्बाकू और सुंघनी की तम्बाकू में 25 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से घटती हो जायगी। लेकिन तम्बाकू के डण्ठलों के सम्बन्ध में मौजूदा 65 पैसे प्रति किलोग्राम के स्थान पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मशीनों के द्वारा बनायी जाने वाली बीड़ियों पर 3.60 रुपये प्रति एक हजार की दर से शुल्क अब भी लगा हुआ है। मैं हाथ से बनायी जाने वाली बीड़ियों पर भी 1 रुपये प्रति एक हजार की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें से 80 पैसे बुनियादी शुल्क के रूप में और 20 पैसे बित्री कर के बदले लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के स्थान में होंगे। प्रशासनिक सुविधा के लिए यह शुल्क उन्हीं बीड़ियों पर लगेगा जो किसी ब्रांड के नाम से बेची जाती हैं। मशीनों से बनी बीड़ी पर, तदनुसार, शुल्क 3.60 रुपये से बढ़ाकर 4.60 रुपये प्रति हजार कर दिया जायगा। इस तरह जो लोग किसी खास ब्रांड की बीड़ी नहीं पीते और हाथ की बनी बिना ब्राण्ड वाली बीड़ी पीते हैं वह लोग बीड़ी की तम्बाकू पर शुल्क के घटाये जाने से लाभ में रहेंगे। मैं ब्रांडों के नाम से बिकने वाली खाने की तम्बाकू और सुंघनी पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन खाने वाली तम्बाकू के मामले में, जिसकी कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक न हो, 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायगी अगर ब्रांड वाली बीड़ी पीने वाले को ज्यादा कर देने के लिए कहा जा रहा है तो न्याय की मांग यह है कि पाइप पीने वालों और सिगरेट पीने वालों को भी विकास प्रयत्नों में सहायता देने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं सिगरेटों पर प्रभावी शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। अगर सिगरेटों की कीमत 10 रुपये प्रति हजार की कीमत से ज्यादा न हो तो उन सिगरेटों पर मूल्यानुसार बुनियादी शुल्क की प्रभावी दरें इस समय 85 प्रतिशत हैं जिसमें 10 रुपये प्रति हजार से ऊपर के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये या उसके भाग के लिए 3 प्रतिशत मूल्यानुसार की वृद्धि हो जाती है। इस शुल्क में, कीमतों के सभी स्तरों पर 5 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से वृद्धि की जायगी, लेकिन बुनियादी शुल्क की उच्चतम सीमा 250 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर पर बनी रहेगी। इसी प्रकार मैं स्मोकिंग मक्सचर के बुनियादी प्रभावी शुल्क में 5 प्रतिशत मूल्यानुसार की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। अनमैन्यूफैक्चर्ड तम्बाकू पर लगे शुल्क के युक्तिसंगत बनाये जाने के कारण राजस्व में 8.25 करोड़ रुपये तक की कमी हो जायगी। लेकिन तम्बाकू और तम्बाकू से बनी वस्तुओं से 26.88 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 10. राजस्व जुटाने के लिए और युक्तिकरण के उपाय के रूप में, मैं रेयन और सिंथेटिक यार्न (जिसमें ब्लेंडेड यार्न भी शामिल है) तथा रेयन और कृत्रिम रेशम के कपड़े पर लगने वाले शुल्क का दरों में फेरबदल करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं नकली रेशम के कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के भार को आंशिक रूप से कपड़े की स्टेज से हटा कर यार्न की स्टेज पर डालना चाहता हूँ क्योंकि यार्न को स्टेज पर राजस्व का संग्रह प्रशासनिक दृष्टि से अधिक आसान है और उससे बच निकलने के रास्ते कम

होते हैं। नकली रेशम के कपड़े पर विक्री-कर के बदले लगाया गया। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और हथकरघा उपर पर पहले का तब हथकरघा के स्टेज पर ही लगाया जाता रहेगा; लेकिन नकली रेशम के कपड़े पर 15 रुपये से बर्ग गज अधिक कीमत वाले कपड़े के मामलों को छोड़ कर, कोई बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। इससे राजस्व में 22 करोड़ रुपये की कमी होगी। इस कमी को दूर करने के लिए और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए मैं रेयन और सिंथेटिक यार्न पर लगने वाले शुल्क में समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं टेक्सचर्ड यार्न पर, उसके निर्माण में इस्तेमाल किये जाने वाले आधारभूत यार्न पर लगने वाले शुल्क के अलावा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम का एक नया शुल्क लगाने का और बुने हुए कपड़े के सम्बन्ध में मौजूदा रियायतें वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। टायर काष्ठ यार्न और ग्लास यार्न के, जो औद्योगिक उत्पादन के काम आता है, और अपशिष्ट पदार्थों के शुल्क में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है।

2. 11. मैं सुपरफाइन और फाइन सूती यार्न पर, जो कम्पोजिट मिलों द्वारा, बिजली चालित करघों द्वारा; और सूती कपड़ा उद्योग के हौजरी और सिलाई के धागे के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, लगने वाले मौजूदा शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। सूती यार्न के शुल्क की दरों में वृद्धि के क्रम में, मैं कम्पोजिट मिलों द्वारा अपने द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सूती यार्न और मिश्रित यार्न के सम्बन्ध में अदा की जाने वाली कम्पाउण्ड लेवी की दरों में समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उद्देश्य से कि यार्न पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि से हथकरघा क्षेत्र को आघात न पहुँचे, मिलों द्वारा स्ट्रेट रील हैक्स के रूप में निकासी किये गये यार्न पर, जो अधिकांशतः हथकरघा क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लगने वाले शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा।

2. 12. 1973 में सरकार ने हथकरघा की समस्याओं की गहराई से जांच करने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त अध्ययन दल की नियुक्ति की थी। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि बिजली चालित करघा इस स्थिति में है कि वे हथकरघों के उचित बाजार में अधिक सस्ते दामों पर माल बेच सकते हैं; दल ने यह सिफारिश की थी कि बिजली चालित करघों पर लगने वाली कम्पाउण्ड लेवी 300 रुपये प्रति करघा प्रतिवर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। चाहे किसी एकक में करघों की संख्या कितनी ही क्यों न हो। इस मामले की सरकार ने ध्यानपूर्वक जांच की है और अब मैं उन सभी एककों पर जिनमें से प्रत्येक में 50 से कम बिजली चालित करघे हों, बिजली चालित करघों पर लगी कम्पाउण्ड लेवी को बढ़ा कर 200 रुपये प्रति करघा प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूँ।

2. 13. इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ मिलें फेंट्स और रैम्स की निकासी के लिए निर्धारित शुल्क की मौजूदा रियायती दरों का अनुचित लाभ उठाती हैं। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए, सूती फेंट्स और रैम्स के लिए शुल्कों का एक वो-स्तरीय ढांचा लागू करने का प्रस्ताव है, निचला स्तर एक निर्धारित सीमा तक निकासी किये गये फेंट्स और रैम्स पर लागू होगा और उच्च स्तर उस सीमा से ऊपर की निकासी पर लागू होगा। कपड़े सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों से 49. 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 14. हालांकि एयर कंडीशनरों पर पहले ही 75 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगता है, फिर भी मैं इसको बढ़ा कर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, मैं रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग सैन्यन्तों और मशीनों के हिस्सों पर लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ा कर 125 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन रेफ्रिजरेटिंग और रेफ्रिजरेटिंग मशीनों और उपकरणों तथा एयर कूलरों के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज प्लांटों, अस्पतालों और कारखानों के लिए रेफ्रिजरेटिंग मशीनों के हिस्सों पर भी मौजूदा रियायती दर से ही शुल्क लगता रहेगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि श्रंगार और प्रसाधन

सामग्री के बुनियादी शुल्क की 30 प्रतिशत की मूल्यानुसार मौजूदा दर को बढ़ा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाय। चूंकि इस मद पर प्रभावी बुनियादी शुल्क की 50 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क भी लगता है इसलिए शुल्क में कुल 15 प्रतिशत की मूल्यानुसार वृद्धि होगी। शैम्पू पर भी अब से 40 प्रतिशत का बुनियादी शुल्क लगेगा।

2. 15. भाग्य से जिनके पास इतनी काफी नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं हैं कि उन्हें सेफ और स्ट्रांग बाक्स खरीदने की जरूरत है उन्हें मेरे इस अगले प्रस्ताव के प्रति कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सेफ, स्ट्रांग बाक्स और ऐसी वस्तुओं के शुल्क की मूल्यानुसार दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाय। एयर कंडीशनरों और उनके हिस्सों, श्रैंगार और प्रसाधन सामग्री और सेफ और स्ट्रांग बक्सों और ऐसी अन्य वस्तुओं के शुल्क में वृद्धि करने के मेरे प्रस्तावों के संयुक्त परिणाम के तौर पर राजस्व में 7.65 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है।

2. 16. राजस्व जुटाने के उपाय के रूप में, मैं सिथेटिक आर्गेनिक डाई स्टाफ और सिथेटिक आर्गेनिक डेरीवेटिव्स, चीनी मिट्टी के सामान, पोर्सिलेन के सामान और कांच तथा कांच के सामान पर, प्रयोगशाला में काम आने वाले कांच के सामान को छोड़ कर, लगने वाले प्रभावी शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा चीनी के सामान और पोर्सिलेन के सामान के छोटे पैमाने के निर्माताओं को शुल्क में रियायत देने के मौजूदा आधार में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है, लेकिन यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 1975 से लागू होंगे। सिथेटिक आर्गेनिक डाईस्टफ, कांच और कांच के सामान और चीनी मिट्टी के सामान और पोर्सिलेन के सामान के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से 10.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 17. मैं पैकिंग और रैपिंग पेपर, पल्प बोर्ड और डुप्लेक्स तथा ट्रिप्लेक्स बोर्डों पर लगने वाले शुल्क की दर को 80 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 1.20 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 9.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 18. मैं बिजली के तारों और केबलों के—उनको छोड़ कर जिनका इस्तेमाल दूर-संचार और उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किया जाता है—प्रभावी शुल्क में 2½ से 5 प्रतिशत मूल्यानुसार तक की दरों से वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं बिजली के पंखों के शुल्क में भी मामूली सी वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं, लेकिन औद्योगिक पंखों के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। बिजली के तारों, केबलों और पंखों के शुल्क में प्रस्तावित वृद्धियों से 4.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 19. ग्रामोफोनों, रेकार्ड प्लेयर्स, टेप रिकार्डर्स, स्थायी चुम्बकों, गाड़ियों के टायरों, मोटर-गाड़ियों के हिस्सों, वूल टाप्स के सम्बन्ध में शुल्क दरों का युक्तिकरण करने और छूट अधिसूचित करने, स बुन के उत्पादन में चावल की भूसी के तेल और माइनर आयल के इस्तेमाल के लिए और वनस्पति उत्पादों के उत्पादन के लिए बिनोले के तेल के इस्तेमाल के लिए रियायतों का प्रस्ताव किया गया है। मैं एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की शुल्क-दरों को युक्ति संगत बनाने और रंगीन व सादा दोनों तरह की फिल्मों की मौजूदा दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इन सभी उपायों से 6.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 20. 'स्केल्प' शब्द के अर्थ के बारे में भ्रम को दूर करने के लिए मैं टैरिफ की मद 26 ए० ए० के अन्त में एक परिभाषा देने और इसी परिभाषा के अनुसार पिछली लेवी व शुल्कों के निर्धारण और संग्रह को विधि सम्मत बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

2. 21. चूकि आयात किये गये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों और एनोडों की कीमत और इनको देश में तैयार किये जाने पर होने वाले खर्च दोनों में अन्तर होता है इसलिए मैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों और एनोडों पर 15 प्रतिशत का मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 1.50 करोड़ रुपयों का राजस्व मिलेगा।

2. 22. मैं अब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने की एक नई धारणा पर आता हूँ। अब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के टैरिफ में कुछ निश्चित की गयी चीजें आती हैं। कर योग्य चीजों की सीमा को व्यापक बनाने और भविष्य में रास्जब इकट्ठा करने की कोशिशों के लिए अधिक विष्वसनीय सूचना प्राप्त करने के लिए मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की अनुसूची में एक नयी मद शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ जो कुछेक अपवादों को छोड़ कर विक्री या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बनायी गयी सभी वस्तुओं को जो इस अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल कर लेगी। इस नयी मद के अन्तर्गत आने वाली सभी चीजों पर 1 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सांकेतिक शुल्क लगेगा। टैरिफ की इस मद में फैक्टरीज एक्ट, 1948 की परिभाषा में आने वाली सभी फैक्ट्रियों का उत्पादन शामिल होगा लेकिन मैं प्रशासनिक सुविधा के लिए बिजली से चलने वाली ऐसे फैक्ट्रियों को शामिल नहीं करूंगा जिनमें 49 से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करते। इसी तरह बिजली के बिना चलने वाली ऐसी फैक्ट्रियों का उत्पादन भी शामिल नहीं होगा जिनमें 99 से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करते। शुल्क लगाने को और अधिक सरल बनाने के लिए मैं इस मद में आने वाले अन्तर्वर्ती उत्पादों और हिस्सों को शामिल नहीं करूंगा जो किसी फैक्टरी में पैदा किये जाते हैं और पूर्ण निर्मित माल तैयार करने के लिए उसी फैक्टरी में इस्तेमाल कर लिये जाते हैं। इस नयी मद से मिलते जुलते आयात किये गये माल पर कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगेगा। यह लेवी निश्चय ही एक प्रयोगात्मक उपाय है। मेरा अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष 24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

2. 23. 31 मार्च, 1975 तक वैध 1974 के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये सहायक उत्पाद शुल्क को 30 जून, 1976 तक बढ़ाया जा रहा है। कुछ मदों पर प्रस्तावित बुनियादी शुल्क में वृद्धि के कारण मुख्यतः सहायक शुल्कों से अतिरिक्त आय होगी जो अनुमानतः 5.34 करोड़ रुपये होगी। यह रकम उल्लिखित संबंध मदों के अन्तर्गत राजस्व अनुमान में शामिल कर ली गयी है।

2. 24. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अन्तर्गत ऊपर दिये गये प्रस्तावों से 250.47 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होगी। इस में संघ सरकार का भाग 194.81 करोड़ रुपये और राज्यों की सरकारों का भाग 55.66 करोड़ रुपये होगा।

आयात शुल्क

2. 25. मैं सीमा शुल्कों की दरों में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं करता। लेकिन अलौह धातुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए मैं तांबे के प्रतिसंतुलनकारी शुल्क में 3,500 रुपये प्रति टन और जस्ते के प्रतिसंतुलनकारी शुल्क में 2,125 रुपये प्रति टन की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। इन परिवर्तनों से 24.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 26. ऊपर जिन कुछ मदों पर मैंने सीमा शुल्कों की वृद्धि की है उससे आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में 9.55 करोड़ की वृद्धि होगी।

2. 27. 1974 के वित्त अधिनियम के अधीन लगे सहायक सीमा शुल्कों को 30 जून, 1976 तक बढ़ाया जा रहा है और इस लेवी की प्रभावी दरों में कोई फेर बदल नहीं की गयी है।

2. 28. [मैंने जो विभिन्न प्रस्ताव किये हैं उनसे सीमा शुल्क के राजस्व में 34.05 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी ।

2. 29. संघ उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों से मिलाकर केन्द्र को 1975-76 ; 228.86 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे ।

केन्द्रीय बिक्री कर

2. 30. अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं एक प्रस्ताव का उल्लेख कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं राज्यों और संघ क्षेत्रों की सरकारों के लाभ के लिए साधनों का संग्रह कर रहा हूँ । अन्तर्राज्यीय चीजों की बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर का दर को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत किया है और इसी के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित चीजों के स्थानीय बिक्री कर के सम्बन्ध में निर्धारित उच्चतम सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप, जो 1 जुलाई, 1975 से लागू होगा, उन संघ क्षेत्रों के लिए, जिनका राजस्व भारत की समेकित निधि का भाग होता है, 1975-76 में 1.75 करोड़ रुपये की वसूली होगी । इस उपाय से 1975-76 में राज्यों को 38.25 करोड़ रुपये तक का लाभ होगा ।

III

3. 1. संक्षेप में, जहां तक केन्द्रीय बजट का सम्बन्ध है विभिन्न प्रस्तावों से 1975-76 के लिए 239 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और बजट का 464 करोड़ रुपये का घाटा कम हो कर 225 करोड़ रुपये तक रह जायगा ।

3. 2. इस प्रकार इस बजट का घाटा मामूली रखा गया है । अन्न, बिजली और ईंधन के ज्यादा मात्रा में मिल सकने की सम्भावना से इतने घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में मूल्यवृद्धि के दबावों के और ज्यादा बढ़ने की सम्भावना नहीं होगी ।

3. 3. इस बजट को बनाने में मेरी सबसे बड़ी चिन्ता यह रही है कि अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी लगाने की दर में वृद्धि लाकर उत्पादन बढ़ाया जाय । हमने अपने लिए जो लक्ष्य निश्चित किये हैं उनको प्राप्त करने के साधनों का कारगर होना मोटे तोर पर समाज के सभी वर्गों की इच्छा पर निर्भर करता है कि लोग इस समान लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना कितना सहयोग देते हैं ।

3. 4. आइये, हम सभी, चाहे सरकार में हों, विधान सभाओं में या बाहर, इस घड़ी में इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में फिर से जुट जाय और अपने आचरण में ऐसा संयम और संकल्प ले आयें जिसकी कि इस समय ज़रूरत है ।

PART 'B' OF THE BUDGET SPEECH 1975-76

DIRECT TAXES

1.1. Sir, let me present first my proposals in the field of direct taxes. Honourable Members will recall that the rates of income-tax on personal incomes were reduced last year on the basis of a recommendation of the Direct Taxes Enquiry Committee. It was expected that this would lead to better tax compliance. I think the policy adopted last year should be given a fair trial. I, accordingly, propose not to make any change in the rates of income-tax in the case of non-corporate taxpayers.

1.2. At present, the basic rate of income-tax in the case of closely-held industrial companies stands at 55 per cent on the first Rs. 2 lakhs of taxable income, and 60 per cent on the balance. On the analogy of the rate structure

applicable to the widely-held companies, I propose to modify this provision so as to apply the higher rate of 60 per cent on the entire income of such closely-held companies in cases where the taxable income exceeds Rs. 2 lakhs, subject, however, to the usual marginal relief. This measure will yield Rs. 4 crores in a full year and Rs. 3 crores in 1975-76. There will be no change in the rates of income-tax in the case of other categories of companies.

1.3. The levy of a tax under the Interest-tax Act, 1974 on interest received by scheduled banks has had the effect of increasing, on an average, the cost of borrowings from scheduled banks by about one per cent. The levy of this tax has, therefore, made the acceptance of deposits by non-banking non-financial companies from the public all the more attractive, specially in the context of the selective credit control measures adopted by the Reserve Bank. Some corrective by way of a disincentive to borrowings from the public by these companies seems to be indicated so that credit planning according to the priorities laid down by the Government is not defeated. I propose, therefore, that in computing the taxable income of non-banking non-financial companies, only 85 per cent of the interest paid by them on public deposits will be allowed as expenditure for tax purposes. This measure will yield Rs. 10 crores in a full year and Rs. 7.5 crores in 1975-76.

1.4. The tax holiday concession is at present available in respect of industrial undertakings that go into production before 1st April, 1978 and ships which are brought into use before that date. I propose to extend the concession in these cases for a further period of five years. This concession is at present available to approved hotels irrespective of the date by which they may start functioning. I find no justification for giving preferential treatment to approved hotels over industrial undertakings and ships. I therefore propose to restrict the concession in the case of approved hotels to cases where these hotels start functioning before 1st April, 1981.

1.5. At present, dividends declared by companies out of their tax holiday profits are exempt in the hands of shareholders. Experience has shown that this provision is difficult to administer, since any change in the quantum of income of the company distributing dividends requires modification of the assessments of all its shareholders, who may be residing in different parts of the country. I, therefore, propose to withdraw the exemption in respect of dividends paid by companies out of their tax holiday profits attributable to the extended period. Shareholders will, however, not stand to lose, since I propose to increase the quantum of tax holiday profits in the case of companies from 6 per cent to 7.5 per cent per annum of the capital employed in new industrial undertakings, ships or hotels.

1.6. In order to channelise corporate savings into high priority industries, I propose to exempt from income-tax, inter-corporate dividends derived by domestic companies from new companies engaged in the manufacture of fertilisers, pesticides, paper and cement.

1.7. As Honourable Members are aware, initial depreciation allowance at the rate of 20 per cent of the cost of machinery and plant is allowed in respect of the priority industries listed in the Ninth Schedule to the Income-tax Act. Having regard to the importance of pesticides to our economy for increasing agricultural production, I propose to extend the benefit of initial depreciation allowance to the pesticides industry also.

1.8. As another measure for promoting investment in desired areas, I propose to exempt from wealth-tax for a period of five years investment in equity shares of new companies engaged in priority industries listed in the Ninth Schedule to the Income-tax Act.

1.9. Under a provision made in the Finance Act, 1974, development rebate is admissible in respect of ships which were ordered before 1st December, 1973 if such ships are acquired before 1st June, 1975. In view of the time lag involved in acquiring ships, I propose to extend this concession to ships which will be acquired before 1st January, 1977, provided orders for their acquisition were placed before 1st December, 1973.

1.10. Under the existing law, a deduction equal to 20 per cent of the profits and gains derived from the business of publication of books is allowed in computing taxable income. This concession is available for a period of five years ending with the assessment year 1975-76. I propose to extend this concession for another five years.

1.11. Our development efforts can be sustained only through promotion of savings. I have, therefore, decided to liberalise the concession currently available under the Income-tax Act in respect of long-term savings through provident funds, life insurance, etc. so as to allow a deduction in respect of 100 per cent of the first Rs. 4,000 of the qualifying savings plus 50 per cent of the next Rs. 6,000 of such savings plus 40 per cent of the balance. This measure will result in a revenue loss of Rs. 8 crores in a full year and Rs. 6 crores in 1975-76.

1.12. Frequent withdrawals are made from Government Provident Funds. I have, therefore, decided to introduce an incentive bonus scheme to benefit those Government employees who do not withdraw any amount from their provident fund accounts during the year. The bonus will be allowed on the subscriptions made during that year and will be calculated at the rate of 3 per cent for employees drawing pay up to Rs. 500 per month and 1 per cent for employees drawing pay above Rs. 500 per month.

1.13. Honourable Members will notice that a package of measures has been proposed for improving the investment climate, namely, extension of tax holiday, exemption of inter-corporate dividends derived from new companies engaged in high priority industries, exemption from wealth-tax of equity shares in new companies engaged in certain priority industries, and incentives to greater savings. Despite the severe constraint of resources, I have thought it advisable to propose these fiscal incentives as, in my view, investment in priority sectors has to be encouraged now if we are not to compound our difficulties in the future. These fiscal measures will reinforce the other measures that the Government have taken for encouraging greater production in certain vital sectors.

1.14. In order to give some relief to middle class families who have to bear the burden of providing higher education to their children, I propose to allow a deduction in respect of expenses incurred by individuals in this regard. In respect of children attending degree or post-graduate courses in medicine, engineering or other technical subjects, the amount of deduction will be Rs. 1,000 per child and in respect of children attending degree or post-graduate courses in other subjects or diploma courses in medicine, engineering or other technical subjects, the amount of deduction will be Rs. 500 per child. The new concession will be available in the case of individuals whose gross total income does not exceed Rs. 12,000 per annum and restricted to two children in any case. This measure will result in a reduction of revenue of Rs. 7 crores in a full year and a little over Rs. 4 crores in 1975-76.

1.15. At present, income from live-stock breeding and poultry and dairy farming is exempt from income-tax. This exemption is prone to abuse by showing income which would otherwise be chargeable to tax as exempt income. I, accordingly, propose to restrict the exemption to Rs. 10,000 in a year. This will mean an additional revenue of Rs. 2 crores in a full year and Rs. 1.2 crores in the financial year 1975-76.

1.16. I propose to exempt from income-tax retrenchment compensation paid to workmen under the Industrial Disputes Act or other similar laws up to a maximum of Rs. 20,000.

1.17. There are at present certain income-tax exemption limits applying to salaried assesses relating to house rent allowance and leave travel concessions. These are being liberalised. Indian technicians employed abroad are also proposed to be given some tax relief.

1.18. In order to simplify and rationalise the procedure for assessment of foreign shipping enterprises, the accounts of which are not easily accessible, I propose to provide that the income of such enterprises shall be taken at 7.5 per cent of the aggregate of their gross earnings from traffic originating in India and other earnings received in India. This change is also in line with the practice in some other countries.

1.19. At present, contributions made to an approved gratuity fund are allowed as deduction in computing the taxable income. A doubt has been expressed that, under the relevant provisions as presently worded, provisions made in the books of account by taxpayers would also qualify for deduction. This is clearly not the intention. Since the employer continues to have control over these funds, I propose to provide specifically that no deduction for tax purposes will be allowed in respect of such provisions made to provide for future gratuities.

1.20. With a view to curtailing ostentatious expenditure in business and professions, I propose to deny depreciation in respect of imported cars which are acquired after 28th February, 1975. Simultaneously, I propose to allow full depreciation in respect of indigenous cars, irrespective of their cost.

1.21. At present, trees standing on agricultural land do not qualify for exemption from wealth-tax. In order to encourage planting and conservation of trees, I propose to exempt the value of trees standing on agricultural land from wealth-tax, except in respect of orchards and plantations.

1.22. Under Corporation Tax, the full year effect of the proposals is Rs. 14.0 crores and the yield for 1975-76 will be Rs. 10.5 crores. As a result of the concessions given, there will be a net reduction of Rs. 13.0 crores under Income-tax in a full year and Rs. 9.0 crores in 1975-76. The impact of this reduction in 1975-76 on the Central revenues will be Rs. 2.26 crores.

II

INDIRECT TAXES

2.1. I now come to my proposals relating to Indirect Taxes.

2.2. While I have had to impose levies covering a wide range of commodities, I have done my best to reduce to the minimum the burden that would fall on the more vulnerable sections of the community. It has also been my endeavour to select items which largely figure in the pattern of consumption of the more affluent sections of society. I have also attempted to select those commodities which are significant in our export efforts so that consumption is thereby reduced in the home market releasing an export surplus which would earn us valuable foreign exchange.

EXCISE DUTIES

2.3. The recent spurt in the price of sugar in the international market provides us an excellent opportunity to increase our exports of this commodity, even at some sacrifice. With a view to reducing consumption of sugar for less essential uses and releasing more quantities for export, I propose that the Basic excise duty on free sale sugar may be stepped up from 30 per cent *ad valorem* to 37½ per cent *ad valorem*. I do not propose to make any change in the present effective rate of duty on levy sugar, which now accounts for 65 per cent of the total internal releases, so that the average citizen is assured of his quota of sugar at a reasonable price. The proposed increase in duty on free sale sugar will yield an additional revenue of Rs. 30.25 crores.

2.4. Khandsari sugar is at present chargeable to a duty of 17.5 per cent *ad valorem*. However, there is a scheme of compounded levy under which Khandsari sugar units opting for the scheme pay a fixed sum by way of duty for every week of working, depending on the number and size of the centrifuges used by them. As the compounded levy results in a disproportionately low duty incidence on these Khandsari units in comparison with the incidence on regular vacuum pan sugar mills, I propose to withdraw the compounded levy scheme. All the Khandsari units will, hereafter, work under the normal Central Excise procedure and pay duty at 17.5 per cent *ad valorem*. From this proposal I expect to raise an additional revenue of Rs. 19.60 crores.

2.5. The duty on tea produced in the various Zones has remained unchanged for the last five years. Tea prices both in the Indian and London auctions have substantially risen during this period. I, therefore, propose to increase the existing basic duty on loose tea produced in Zones I, II, IV and V by 10 to 15 paise per kg. Tea of Zone III at present bears the highest rate of duty and there is need for giving some relief because of the low yield and the high cost of cultivation. As more than 90 per cent of the Tea produced in this Zone is exported and since the price increases in respect of these teas have been the least, I propose to reduce the present basic duty for this Zone by 10 paise per Kg. Apart from bringing in revenue, the proposed increase in duty on Teas of Zones I, II, IV and V will help in making more tea available for export. With a view to ensure that the increase in excise duty on tea does not hit exports, I also propose to raise the ceiling limit on the quantum of rebate admissible for exported teas under the present scheme from the existing level of 75 paise per kilogram to 85 paise per kilogram. The net effect of the proposed changes will be an additional revenue of Rs. 3.40 crores.

2.6. Cement is another potential foreign exchange earner, and for similar reasons, I propose to step up the basic duty on cement from 30 per cent *ad valorem* to 35 per cent *ad valorem*. This proposal will yield an additional revenue of Rs. 15.95 crores.

2.7. The import of crude petroleum and petroleum products continues to demand a large share of the total available foreign exchange resources. I felt that so long as energy shortages persist, there is a case for making petroleum products more expensive so as to promote greater economy and efficiency in their use. Against this background, the duty on motor spirit is proposed to be raised by 10 paise per litre. I also propose to increase the duty on furnace oil to induce replacement of oil-fired equipment by coal-fired equipment. Such a duty will be an added reason to replace obsolescent equipment with modern efficient units, even in installations which continue to use oil. However, taking into consideration its use by various industries, the increase proposed is modest—a little less than 3 paise per litre. Low Sulphur Heavy Stock used for electricity generation will, however, continue to be exempt as at present. These levies on petroleum products will together yield an additional revenue of Rs. 26.00 crores.

2.8. There has been a fall in the proportion of aluminium of electrical conductor grade produced in recent years compared to the commercial grade. Since it is of paramount importance that there should be no shortage of aluminium of electrical conductor grade required by various power systems, I propose to increase by Rs. 2,000 per tonne the excise duty on commercial grade aluminium thereby providing encouragement for greater production of electrical conductor grade aluminium. The proposed increase in duty on aluminium will yield an additional revenue of Rs. 15.00 crores.

2.9. I shall now turn to a product on which all Finance Ministers have had to rely heavily namely, tobacco and its products. The Tobacco Excise Tariff Committee has recommended a uniform tariff rate for all forms of non-flue-cured unmanufactured tobacco, other than that used for the manufacture of cigarettes, supplemented by a low rate of excise duty on certain specified tobacco products namely, biris and chewing tobacco sold under a brand name, and snuff. Following the Committee's recommendation, I propose to levy a uniform total excise duty of Rs. 3 per kilogram on non-flue-cured unmanufactured tobacco other than that used for the manufacture of cigarettes. This will mean a reduction of Rs. 1.60 per kg. in the total duty for biri tobacco, and of Re. 0.25 per kg. for hookah, chewing and snuff tobacco. However, in the case of stalks I propose to fix the duty at Rs. 2 per kg. against the present rate of Re. 0.65 per kg. There is already a duty of Rs. 3.60 per thousand on biris manufactured with the aid of machines. I now propose to levy a duty of Re. 1 per thousand on handmade biris also, of which 80 paise will be in the form of Basic duty and 20 paise in the form of Additional excise duty in lieu of sales tax. For the sake of administrative convenience, this levy will be restricted to biris sold under brand names. The duty on machine made biris will be correspondingly stepped up from Rs. 3.60 to Rs. 4.60 per thousand. It will be noticed that those smokers who are not unduly discriminating and are content with unbranded handmade biris which bear no excise duty should benefit from the reduction in duty on biri tobacco. I also propose to levy a duty of 10 per cent *ad valorem* on chewing tobacco sold under brand names and on snuff. An exemption to the extent of 5 per cent will, however, be provided in respect of chewing tobacco whose value does not exceed Rs. 10 per kg. If the smokers of branded biris are called upon to pay more, equity requires that those smoking pipes and cigarettes should not be denied the privilege of helping the developmental effort. Accordingly, I propose to raise the effective duty on cigarettes also. The effective Basic duty on cigarettes is now 85 per cent *ad valorem*, if the value of the cigarettes does not exceed Rs. 10 per thousand, and increases by 3 per cent *ad valorem* for every additional rupee or part thereof in excess of Rs. 10 per thousand. This duty will be increased by 5 per cent *ad valorem* at all price level except that the ceiling level of Basic duty will continue to remain at 250 per cent *ad valorem*. Similarly I also propose to raise the Basic effective duty on smoking mixtures by 5 per cent *ad valorem*. On account of the rationalisation of duty on unmanufactured tobacco there will be a reduction of revenue to the extent of Rs. 8.25 crores. But the net additional revenue from tobacco and tobacco products will be Rs. 26.88 crores.

2.10. Both for raising revenues and as a measure of rationalisation I propose to readjust the rates of duty on rayon and synthetic yarns (including blended yarns), and on rayon or artificial silk fabrics. I propose to shift partially the burden of excise duty on artsilk fabrics from the fabric stage to the yarn stage, since collection of revenue at the yarn stage is administratively easier and provides fewer loopholes. The additional excise duty levied on artsilk fabrics in

lieu of sales-tax, and the handloom cess, will continue to be levied at the fabric stage; but there will be no basic excise duty on art-silk fabrics except in the case of those fabrics whose value exceeds Rs. 15 per sq. metre. This will result in a loss of revenue of Rs. 22 crores; to neutralise this loss, and to earn additional revenue, I propose to increase the duty on rayon and synthetic yarns suitably. I also propose to levy a new duty of Rs. 20 per kg. on textured yarns in addition to the duty leviable on base yarn used in their manufacture, and to withdraw the existing concessions on knitted fabrics. No increase is proposed on tyre cord yarn and on glass yarn which go into industrial production, and on wastes.

2.11. I, propose to raise the existing duties on superfine and fine cotton yarns which are used by the composite mills, by powerlooms, and in the hosiery and sewing thread sectors of the cotton textile industry. As a sequel to increase in the rates of duty on cotton yarn I also propose to raise suitably the rates of compounded levy paid by composite mills on cotton yarn and mixed yarn used by them. In order that the increases in yarn duty may not hit the handlooms, the duty on yarn cleared from the mills in the form of straight reel hanks used mostly by the handloom sector is being kept unchanged.

2.12. In 1973 Government appointed a High Powered Study Team to examine in depth the problems of the Handloom Industry. This body has observed in its report that powerlooms are in a position to undercut handlooms in their legitimate market, and has recommended that the compounded levy on powerlooms may be fixed at Rs. 300 per powerloom per annum irrespective of the number of looms in a unit. The matter has been carefully examined by Government and I now propose to increase the compounded levy on powerlooms to Rs. 200 per loom per annum on all those units with less than 50 powerlooms each.

2.13. There are reports that some mills take undue advantage of existing concessional rates of duty prescribed for clearance of fents and rags. With a view to eliminate this abuse, a two-tier duty structure is proposed to be introduced for cotton fents and rags, the lower level applying to fents and rags cleared up to a prescribed limit, and the higher level, to clearances above that limit. The various proposals on textiles will yield an additional revenue of Rs. 49.10 crores.

2.14. Although air conditioners already carry a duty of 75 per cent *ad valorem*. I propose to raise this level to 100 per cent *ad valorem*. I similarly propose to raise the duty on parts of refrigerating and air conditionings plants and machinery from 100 per cent *ad valorem* to 125 per cent *ad valorem*. Duty on refrigerators, and refrigerating machinery and appliances as well as Air coolers, is however being kept unchanged. Parts of refrigerating machinery for cold storage plants, hospitals and factories also will continue to pay the present concessional duty. I further propose to raise the Basic duty on Cosmetics and Toilet preparations from the present rate of 30 per cent *ad valorem* to 40 per cent *ad valorem*. Since this item also carries an Auxiliary duty of 50 per cent of the effective Basic duty there will be a total increase of 15 per cent *ad valorem* in the duty. Shampoos will also henceforth pay a Basic duty of 40 per cent.

2.15. Those blessed by fortune to have enough cash and other valuables with them to necessitate the purchase of safes and strong boxes cannot legitimately complain against my next proposal which is to raise the duty on safes, strong boxes and similar articles from 10 per cent *ad valorem* to 20 per cent *ad valorem*. The combined revenue effect of my proposals for increase in duty on air conditioners and parts cosmetic and toilet requisites and safes, strong boxes and the like will be Rs. 7.65 crores.

2.16. As a revenue measure, I propose to increase by 5 per cent the effective duties on synthetic organic dye-stuffs and synthetic organic derivatives, chinaware and porcelainware, and glass and glassware except laboratory glassware. I also propose to make some changes in the existing basis for grant of duty concession to small scale manufacturers of chinaware and porcelainware, but these changes will be made effective only from 1st April, 1975. My proposals regarding synthetic organic dye-stuffs, glass and glassware and chinaware and porcelainware will yield an additional revenue of Rs. 10.20 crores.

2.17. I propose to increase the duty on packing and wrapping paper pulp boards and duplex and triplex boards from 80 paise per kilogram to Rs. 1.20 per kilogram. This will yield an additional revenue of Rs. 9.80 crores.

2.18. I propose to increase the present effective duty on electric wires and cables, excluding those used for telecommunication and high voltage transmission

lines, by varying rates ranging between 2½ and 5 per cent *ad valorem*. I also propose to raise the duty on electric fans marginally, but there will be no increase in the duty on industrial fans. The proposed increases in the duty on electric wires and cables and fans will yield an additional revenue of Rs. 4.30 crores.

2.19. Rationalisation of the tariff entries and exemption notifications relating to gramophones, record players, tape-recorders, permanent magnets, vehicular tyres, components of motor vehicles, wool tops, concessions for the use of rice bran oil and minor oils in the manufacture of soap, and of cotton-seed oil in the manufacture of vegetable products has been proposed. I also propose to rationalise the tariff for exposed cinematograph films and to increase the differential between coloured films on the one hand and black and white films on the other. All these measures will yield an additional revenue of Rs. 6.84 crores.

2.20. To remove doubts about the meaning of the expression "skelp", I propose to add an explanation at the end of Tariff Item 26AA and to validate past levies, assessments and collections of duty in accordance with this explanation.

2.21. As there is a substantial difference between the imported cost of graphite electrodes and anodes and the indigenous cost of production I propose to levy an excise duty of 15 per cent *ad valorem* on graphite electrodes and anodes. This will yield a revenue of Rs. 1.50 crores.

2.22. I now come to a new concept in Central Excise taxation. Hitherto the Central Excise tariff covered only certain specified goods. With a view to widen the coverage of taxable goods and to provide a more dependable information base for future revenue raising exercises, I propose to introduce a new item in the Central Excise Tariff Schedule which, with a few exceptions, will cover all goods produced for sale or other commercial purpose not elsewhere specified in the Schedule. Goods covered under this new item will be chargeable to a nominal duty at the rate of 1 per cent *ad valorem*. While the tariff item will cover the production of all factories as defined in the Factories Act, 1948, I propose for the sake of administrative convenience to exempt the production of those factories which employ not more than 49 workers in the case of power-operated factories, and not more than 99 workers in the case of non-power operated factories. To further simplify the levy, I also propose to exempt from duty intermediate products and component parts falling within this item produced in a factory and consumed within the same factory for the manufacture of finished goods. No countervailing duty will be levied on imported goods corresponding to this new item. This levy is admittedly an experimental measure. I expect that this measure will yield a revenue of Rs. 24.00 crores per annum.

2.23. The auxiliary duty of excise levied under the Finance Act of 1974 valid up to 31st March, 1975 is being continued up to 30th of June, 1976. Mainly on account of the increase in the basic duty proposed on some items, there will be additional accrual of auxiliary duty also, estimated at Rs. 5.34 crores. This amount, however, has been included in the Revenue Estimates under the respective items already mentioned.

2.24. The total effect of all the above proposals relating to Central Excise will be an additional revenue of Rs. 250.47 crores. Of this the Union Government's share will be Rs. 194.81 crores and the States' share Rs. 55.66 crores.

IMPORT DUTIES

2.25. I do not propose any revision of the Customs Tariff rates. But considering the trend of international prices of non-ferrous metals I propose to increase the counter-vailing duty on copper by Rs. 3,500 per tonne and on zinc by Rs. 2,125 per tonne. These changes will yield an additional revenue of Rs. 24.50 crores.

2.26. The increase in Central Excise duty on certain items which I have proposed earlier will lead to a consequential increase of Rs. 9.55 crores in the collection of countervailing duty on imports.

2.27. The auxiliary duties of Customs levied under the Finance Act of 1974 is being continued up to 30th of June, 1976 and the effective rates of this levy remain unchanged.

2.28. The various proposals which I have made will yield an increase of Rs. 34.05 crores in Customs revenue.

2.29. The yield for 1975-76 for the Centre, taking Union Excise Duties and Customs Duties together will be Rs. 228.86 crores.

CENTRAL SALES TAX

2.30. Before I conclude I should mention a proposal which I am making to raise resources for the benefit of the States and Union Territories. The rate of Central Sales-tax on inter-State sales of goods is being raised from 3 per cent to 4 per cent with a corresponding change in the ceiling prescribed in respect of local Sales-tax on goods declared to be of special importance in inter-State trade or commerce. As a result of this proposal being made effective from 1st July, 1975, the additional collections for those Union Territories whose revenues form part of the Consolidated Fund of India will amount to Rs. 1.75 crores in the year 1975-76. The States will benefit to the extent of Rs. 38.25 crores in 1975-76 through this measure.

III

3.1. To sum up, so far as the Union Budget is concerned, the various proposals imply, for 1975-76, additional revenue aggregating Rs. 239 crores. The budgetary gap of Rs. 464 crores, as indicated earlier, will accordingly be scaled down to Rs. 225 crores.

3.2. The budgetary deficit has thus been kept at a modest level. With the improving prospects for the availability of food, power and fuel, this order of deficit is not likely to accentuate inflationary pressures in the economy.

3.3. My major concern in the formulation of this budget has been to stimulate production by stepping up the pace of investment in areas crucial to the healthy growth of the economy. The effectiveness of the measures proposed in achieving the goals that we have set for ourselves will, however, depend in large measure on the willingness of the different sections of the community to contribute their utmost to the common endeavour.

3.4. Let us all then, in Government, the Legislature and outside, rededicate ourselves to this national cause at this juncture and conduct ourselves with that discipline and determination which the occasion demands.

